



लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

प्रायोजित



विश्व कप जीतकर लगा जैसे नया जीवन मिल गया स्पोर्ट्स-12

www.dailypioneer.com

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के विरोध में केंद्र

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा, यह कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है

प्रायोजित समाचार सेवा। नई दिल्ली



सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर उन याचिकाओं का विरोध किया, जिनमें भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि शादी में, अपने जीवनसाथी से उचित यौन संबंध बनाने की निरंतर अपेक्षा की जाती है। इसने स्पष्ट किया कि ऐसी अपेक्षाएं पति को अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देती हैं। हालांकि, केंद्र ने कहा कि बलात्कार विरोधी कानूनों के तहत इस तरह के कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करना अत्यधिक और असंगत हो सकता है। हलफनामे में आगे बताया गया है कि संसद ने पहले ही विवाहित महिला की सहमति को विवाह के भीतर सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय प्रदान किए हैं। अधिका ए.के. शर्मा के माध्यम से दायर जवाबी हलफनामे में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा भारतीय बलात्कार कानून का समर्थन किया, जो पति और पत्नी के बीच यौन संबंधों के लिए अपवाद बनाता है।

समाज पर सीधा असर पड़ता है। केंद्र ने तर्क दिया कि यदि 'वैवाहिक बलात्कार' को भी अपराध घोषित कर दिया जाए तो ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हलफनामे में कहा गया है, इस मुद्दे पर सभी हितधारकों से उचित परामर्श किए बिना या सभी रुझानों के विचारों को ध्यान में रखे बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता... 'वैवाहिक बलात्कार' के रूप में प्रचलित कृत्य को अवैध और अपराध घोषित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि विवाह से महिला को सहमति समाप्त नहीं होती है और इसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम होने चाहिए। हालांकि, विवाह के भीतर इस तरह के उल्लंघन के परिणाम विवाह के बाहर के उल्लंघन से भिन्न होते हैं। इसमें कहा गया है कि सहमति के उल्लंघन के लिए अलग-अलग सजा दी जानी चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ऐसा कृत्य विवाह के भीतर हुआ है या विवाह के बाहर। इन उपायों में विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता को दंडित करने

वाले कानून (भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 498ए), महिलाओं की शील के विरुद्ध कृत्यों को दंडित करने वाले कानून और फरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत उपाय शामिल हैं। हलफनामे में कहा गया है, यौन पहलू पति-पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में से एक है, जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है... हमारे सामाजिक-कानूनी परिवेश में वैवाहिक संस्था की प्रकृति को देखते हुए, यदि विधायिका का यह विचार है कि वैवाहिक संस्था के संरक्षण के लिए, विवाहित अपवाद को बरकरार रखा जाना चाहिए, तो यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय न्यायालय द्वारा अपवाद को रद्द करना उचित नहीं होगा।

यह जवाबी हलफनामा उन याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया है, जिनमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग की गई है। केंद्र ने विवाह संस्था को एक निजी संस्था के रूप में मानने के याचिकाकर्ताओं के दृष्टिकोण की आलोचना की और इस दृष्टिकोण को एकरूपता बताया। इसमें कहा गया है कि एक विवाहित महिला और उसके अपने पति के मामले को अन्य मामलों की तरह ही नहीं माना जा सकता। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस समय मामले पर विचार कर रही है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद 2 के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को 'बलात्कार' में दारपे से बाहर रखा गया है। इसी तरह का प्रावधान हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में भी मौजूद है, जिसने इस साल 1 जुलाई को आईपीसी की जगह ली (शेष पृष्ठ 9)

हरियाणा में प्रचार थमा, भाजपा को झटका दे कांग्रेस में गए अशोक तंवर

दीपक कुमार झा। महेंद्रगढ़ (हरियाणा)/नई दिल्ली



हरियाणा में पांच अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार अभियान बृहस्पतिवार शाम को समाप्त हो गया। सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका तब लगा जब उसके वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर, जो कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में सिरसा से पार्टी के उम्मीदवार थे, बृहस्पतिवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में राहुल गांधी की रैली में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए।

हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले अशोक तंवर के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।

मजे की बात यह है कि कांग्रेस में शामिल होने से कुछ समय पहले सिरसा के पूर्व सांसद, जिसका प्रतिनिधित्व उन्होंने कांग्रेस सदस्य के रूप में किया था, सफाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। जैसे ही राहुल ने अपना भाषण समाप्त किया, मंच से एक घोषणा की गई जिसमें दर्शकों से कुछ मिनट प्रतीक्षा करने को कहा गया और आश्चर्य की बात यह रही कि तंवर मंच पर चले गए और राहुल का अभिवादन किया। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तंवर ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया और पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अभिवादन किया।

तंवर, जिन्हें राहुल का करीबी माना जाता था और उन्होंने 2019 में पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व हुड्डा के साथ मतभेदों के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी और इस बीच उन्होंने टीएमसी के साथ-साथ आप में भी काम किया। भाजपा के लिए प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस 'भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और भाई-भतीजावाद की गारंटी' के लिए खड़ी है। प्रधानमंत्री ने लोगों से भाजपा को वोट देने का आह्वान करते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ऐसी सरकार चुनें जो ऐसे समय में भारत को मजबूत करे जब पूरी दुनिया देश को उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ देख रही है। हरियाणा में अभियान के

लिए अपने अंतिम भाषण में राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी धर्म, भाषा और जाति के आधार पर भाजपा द्वारा फेंकाई जा रही 'नफरत' को जीतने नहीं देगी और हरियाणा के लोगों से विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को बाहर करने की अपील की।

हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए दो करोड़ से अधिक मतदाता अपने मतधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं। चुनाव मैदान में प्रमुख पार्टियां भाजपा, कांग्रेस, आप, इनेलो-बसपा और जेजेपी-आजाद समाज पार्टी हैं। भाजपा ने जहां अपना चुनाव प्रचार 'डबल इंजन' सरकार के कार्यों और प्रदर्शन पर केंद्रित रखा, वहीं कांग्रेस पर आरक्षण, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और

दिल्ली पुलिस ने एल्विष यादव और भारती को किया तलब

प्रायोजित समाचार सेवा। नई दिल्ली



दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े ऐप-आधारित कथित घोटाले में यूट्यूबर एल्विष यादव और कॉमिडियन भारती सिंह और तीन अन्य को तलब किया है, एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया। पुलिस को 500 से अधिक शिकायतें मिलीं, जिनमें आरोप लगाया गया कि कई सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबरों ने अपने पेजों पर एआईबॉक्स मोबाइल एप्लिकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के माध्यम से निवेश करने के लिए लुभाया, अधिकारी ने बताया। पुलिस ने बताया कि घोटाले के मुख्य आरोपी शिवराम (30), जो चेन्नई का निवासी है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत के अनुसार, सौरव जोशी, अभिषेक मरहान, पूरव झा, एल्विष यादव, भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित और दिलराज सिंह रावत सहित सोशल मीडिया प्रभावितों और यूट्यूबरों ने एप्लिकेशन का प्रचार किया और लोगों को ऐप के माध्यम से निवेश करने के लिए लुभाया। पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ स्पेशल सेल) हेमंत तिवारी ने कहा, यह मोबाइल एप्लिकेशन है जो एक सुनियोजित घोटाले का हिस्सा था। डीसीपी ने बताया कि इस ऐप के जरिए आरोपियों ने रोजाना एक से पांच प्रतिशत की गारंटीड रिटर्न का वादा किया था, जो महीने में 30 से 90 प्रतिशत तक होता था। ऐप को फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। ऐप में 30,000 से ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया था। शुरुआती पांच महीनों के दौरान निवेशकों को उच्च (शेष पृष्ठ 9)

भाजपा का आरोप, ड्रग सरगना के कांग्रेस से जुड़े हैं तार

प्रायोजित समाचार सेवा। नई दिल्ली

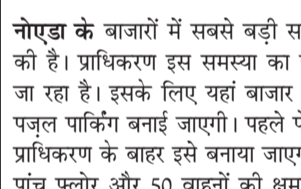


दक्षिण दिल्ली में छापेमारी कर 500 किलोग्राम से अधिक कोकोन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद करने के बाद मुख्य आरोपी तुषार गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 5,600 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की ड्रग्स बरामद की गई हैं। बाद में इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच वाक्यपट्ट शुरू हो गया। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'दिल्ली से 5,600 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की गई हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी तुषार गोयल हैं, जो भारतीय युवा कांग्रेस के आरटीआई सेल के प्रमुख हैं।' त्रिवेदी ने कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि क्या पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में ड्रग मनी का इस्तेमाल किया और क्या गोयल के साथ उसका संबंध व्यापार तक भी है। उन्होंने पूछा कि क्या ड्रा डीलरों और कांग्रेस के बीच कोई समझौता था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें हरियाणा में खुली छूट दी जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पड़ोसी राज्य पंजाब पहले से ही ड्रग्स की गिरफ्त में हैं। त्रिवेदी ने कहा कि गोयल के पास न केवल के सी वेणुगोपाल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, बल्कि उनके पास पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बेटे हुड्डा का मोबाइल नंबर भी है। उन्होंने कहा कि हुड्डा परिवार को भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि आरोपी भारतीय युवा कांग्रेस का पूर्व सदस्य है और उसे दो साल पहले पार्टी ने निष्कासित कर दिया था। (शेष पृष्ठ 9)

नोएडा में पहली बार बनेगी ऑटोमेटेड पजल पार्किंग

पहले फेज में 50 वाहनों की पार्किंग, इसके बाद बाजारों में बनाएंगे, कार निकालने में लगोगा मात्र 3 मिनट

रिंकू यादव। नोएडा



नोएडा के बाजारों में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। प्राधिकरण इस समस्या का हल निकालने जा रहा है। इसके लिए यहां बाजारों में ऑटोमेटेड पजल पार्किंग बनाई जाएगी। पहले फेज में नोएडा प्राधिकरण के बाहर इसे बनाया जाएगा। ये पार्किंग पांच फ्लोर और 50 वाहनों की क्षमता की होगी। इसके बाद दो अन्य बाजारों में इसे बनाया जाएगा। वहां इसकी क्षमता करीब 100 वाहनों की रखी जाएगी। हाल ही में कंपनी ने एक प्रेजेंटेशन प्राधिकरण में दिया था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। अब इसके लिए आरएफपी जारी की जा रही है। ये पार्किंग हाइड्रोलिक पार्किंग से अलग होती है। ऑटोमेटेड पजल पार्किंग एक पजल गेम की तरह है। जिसमें जितने पार्किंग स्लॉट होते हैं उतने ही स्लॉट होते हैं। जो ऊपर, नीचे, दांये और बांये मूव बेल होते हैं। जो ऐसे समझे एक कार पार्किंग के लिए आती है। उसे ग्राउंड के स्लॉट पर खड़ा किया। उसे पांचवें फ्लोर पर कार खड़ी करनी है। ऐसे में पुरा स्लॉट संसर के जरिए कार समेत ऊपर उठेगी और पांचवें फ्लोर पर जाकर सेट हो जाएगी। नीचे खाली स्पेस पर दूसरा स्लॉट ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। इस पूरे काम में करीब 3 से 6 मिनट का समय लगता है। यानी मल्टी लेवल और हाइड्रोलिक या अन्य स्थानों पर पार्किंग करने पर गाड़ी निकालने और खड़ी करने में आपको 15 से 20 मिनट का समय लगता है। लेकिन इसमें कार महज 3 से 6 मिनट पर लग जाती है और बाहर भी आ जाती है। नोएडा में पांच फ्लोर की ऑटोमेटेड पजल पार्किंग बनाने पर विचार किया जा रहा है। इसके प्रत्येक फ्लोर पर पांच कार आसानी से पार्क



हो सकेंगे। इस तरह की पार्किंग के निर्माण में ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होती। बहुत कम स्पेस में ये पांच से छह फ्लोर तक की बन सकती है। ये पूरी पार्किंग सेंसर बेस्ड होती है। इसलिए चोरी से लेकर टूट फूट का खतरा नहीं होता। इसके एक स्लॉट को बनाने में करीब 8 लाख का खर्चा होता है। यानी 50 स्लॉट की पार्किंग करीब 4 करोड़ में बनकर तैयार हो जाएगी। इसके ऑपरेशनल में ज्यादा स्टॉफ की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल ये पार्किंग ऑटोमेटेड है। इसमें गाड़ियां ग्राउंड से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में शिफ्ट होती है। उसी तरह नीचे आती है। ये पूरा काम मशीनों के जरिए होता है। इसलिए इसमें सेंसर लगाए गए हैं। यदि कोई बच्चा

या जानवर गलती से पार्किंग के अंदर आ जाए तो ऑटोमेटिक जहां कार है वहीं स्थिर हो जाएगी। वो नीचे नहीं आएगी ताकि इसके नीचे कोई दब न जाए। इसकी रेंज तय की जा सकती है। जिसे पीली लाइन से इंडीकेट किया जा सकता है। प्राधिकरण ने बताया कि इस तरह की पार्किंग नोएडा के लिए जरूरी हो चुकी है। यहां भीड़भाड़ इलाकों में इस तरह की पार्किंग बनाने पर विचार किया जा रहा है। अभी एक कंपनी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। ये कंपनी दिल्ली में कई स्थानों पर पजल पार्किंग संचालित कर रही है। नोएडा में इसके लिए आरएफपी जारी की जाएगी। जिसमें कंपनी का चयन किया जाएगा।

द्वितीय ब्रह्मचारिणी



दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कल्पण्डलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥ नवरात्र में दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है।



नई सड़कें, नए फ्लाईओवर, रूट विस्तार, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में यातायात की स्थिति भयावह बनी हुई है। लुटियंस जुन, सरदार पटेल मार्ग, धौला कुआं, आरटीआर, मधुरा रोड, तिलक मार्ग, बहादुर शाह मार्ग पिछले तीन दशकों से यातायात के लिए अभिशाप बने हुए हैं। नवरात्र के पहले दिन से ही प्रायोजित न सड़क और यातायात पर अभियान शुरू किया है।

दिल्ली के टैफिक से निपटना इंसानों के बूते की बात नहीं

राजेश कुमार। नई दिल्ली

महरोली-बदरपुर रोड से लेकर विकास मार्ग और इंडेवाला, नजफगढ़ से पीरागढ़ी तक राष्ट्रीय राजधानी में नवरात्र के पहले दिन पीक ऑवर्स के दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि सड़क पर सामना करने वाले लोगों के अनुसार यातायात जाम होना आम बात है। टूटी सड़कें, गड्डे, वाहनों का खराब होना, यातायात का अधिक दबाव और अक्सर प्रमुख मार्गों के रखरखाव के कारण भारी जाम लग रहा है। बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी में नवरात्र के पहले दिन इंडेवाला, कालकाजी, मां काल्यानी देवी मंदिर सहित प्रमुख मंदिरों की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर भारी यातायात के कारण भीड़भाड़ बढ़ गई। विशेषज्ञों का कहना है कि वॉर्ष से स्थिति वैसी ही है, जबकि सड़कों का आकार और मजबूती वही है, लेकिन वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा प्रीत विहार रेड लाइट और नजफगढ़ रोड और ओल्ड पंजा रोड पर चल रहे काम के कारण दोनों कैरिजवे पर कड़कड़ी मोड़ से प्रीत विहार की ओर विकास मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई जीटीके रोड पर जहांगीरपुरी से आजादपुर फ्लाईओवर तक दोनों तरफ यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजादपुर मंडी में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण दो-तीन घंटे तक पूरा यातायात ठप रहा। टैफिक पुलिस की सलाह के अनुसार, क्राउन प्लाजा रेड लाइट पर

नवरात्र आरंभ होने के साथ सड़कों पर बड़ी भीड़

एक बस के खराब होने के कारण ईएसआई अस्पताल से गोविंद पुरी की ओर जाने वाले कैरिजवे में मां आनंदमई मारंग पर यातायात प्रभावित हुआ। महारानी बाग फ्लाईओवर पर पानी के टैंकर के खराब होने के कारण डीएनडी से आग्रम चौक की ओर जाने वाले कैरिजवे में रिंग रोड पर यातायात प्रभावित हुआ। पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक लोडेड ट्रक खराब हो गया, जिससे मधुवन चौक से पीरागढ़ी की ओर जाने वाले कैरिजवे में मेन आउटर रिंग रोड पर भारी जाम लग गया। गड्डों और जलभराव के कारण नांगलोई से टिकरी बाँर्ड की ओर और इसके विपरीत रोहतक रोड पर भी यातायात प्रभावित हुआ। सिविक एजेंसी द्वारा किए जा रहे नाले के काम के कारण सतबरी से महरोली की ओर जाने वाले कैरिजवे में एसएसएन मार्ग पर ट्रैफिक जाम था। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। यातायात पुलिस की सलाह में कहा गया है, पालम फ्लाईओवर पर एक बस के खराब होने के कारण दवाका पालम रोड पर पालम फ्लाईओवर से आईओसी रेड लाइट की ओर (शेष पृष्ठ 9)

केजीएमयू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की होगी स्थापना

लखनऊ में डेंगू के 15 रोगी मिले

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ



लखनऊ जनपद में डेंगू के रोगियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को डेंगू के 15 रोगी सामने आये हैं। जिन इलाकों से रोगियों के मिलने की पुष्टि हुई है उनमें चन्द्रनगर-5, अलीगंज-4, एनके रोड-3, गोसाईगंज-1, इन्द्रानगर-1, टूडियागंज-1) धनात्मक रोगी शामिल हैं। आज लगभग 1034 घंटों एवं आस-पास मच्छरजनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया और कुल 10 घंटों में मच्छरजनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। नगर मलेरिया इकाई एवं जिला मलेरिया अधिकारी की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न स्थलों/भवनों का निरीक्षण किया गया तथा लार्वा रोगी रसायन का छिड़काव किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम लखनऊ की टीमों द्वारा कसाईबाड़ा चौराहा, बदनाम लड्डू चौराहा राजाजीपुरम, डीपीएस जानकीपुरम विस्तार, विराटखण्ड

चौराहा, सन आई हस्पिटल श्रंगार नगर, चौपटिया चौराहा, पटेलनगर मोर्य जनता आटा चक्की, परग चौराहा आषियाना के आस-पास क्षेत्रों में सघन मच्छर रोधी अभियान चलाया गया तथा क्षेत्र में साफ-सफाई, लार्वा रोगी रसायन का छिड़काव एवं फागिग का कार्य कराया गया। क्षेत्रीय जनता को घर के आस-पास पानी जमा न होने, पानी से भरे हुए बर्तन एवं टंकियों को ढक कर रखें, हर सप्ताह कूलर के पानी को खाली करके साफ कपड़े से पोछ कर सूखा एवं साफ करने के बाद ही पुनः प्रयोग में लाने, पूरी बाह के कपड़े पहनने, बच्चों को घर से बाहर निकलने, मच्छर रोधी क्रीम लगाने एवं मच्छर जनित रोगों से बचाव हेतु क्या करें, क्या न करें सम्बंधित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की गयी।

राज्यपाल की उपस्थिति में केजीएमयू, आदित्य बिड़ला कैपिटल फाउंडेशन और केनकिड्स किड्सकेन के बीच हस्ताक्षर



उन्होंने कहा कि जब हम मां को बचाएंगे, तभी बच्चे और परिवार बचेगा। राज्यपाल ने यह भी साझा किया कि जब वह विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में जाती हैं, तो देखती हैं कि 80 प्रतिशत से अधिक पदक और डिग्रियाँ बेटीयों प्राप्त करती हैं। परंतु जब उनकी शारीरिक स्थिति पर नजर डालती हैं तो वे कमजोर दिखती हैं, जो चिंताजनक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बेटियों को कैसर की वैकसीन अवश्य लगवानी चाहिए। अक्सर माता-पिता बेटियों की शादी में लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन जब उनके स्वास्थ्य की बात आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। राज्यपाल ने कहा कि वैकसीनेशन के माध्यम से पहले से ही रोकथाम करना आवश्यक है, क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है, तो इलाज कठिन और महंगा हो जाता है। उन्होंने बताया कि

कहा कि समाज को इस विषय में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां महिलाओं के कैसर की जांच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। शुरूआत में महिलाएं संकोच करती थीं, परंतु जागरूकता के बाद उन्होंने जांच के साथ-साथ इलाज भी करवाया, जो आज भी जारी है।

विश्वविद्यालयों ने पांच-पांच गांवों को गोद लिया है, जहां वैकसीनेशन के कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, उन्होंने ग्रीन आर्मी की ग्रामीण महिलाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि ये महिलाएं, समाज में नशामुक्ति, बच्चों का स्कूल में दाखिला, और अमृत सरोवरो की खुदाई जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इस अवसर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो सोनिया नित्यानंद ने कहा कि राज्यपाल ने हमेशा विश्वविद्यालयों में सीएसआर निधि के तहत क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट रक्त कैसर, अल्पास्तिक एनीमिया, थेलेसीमिया जैसे गंभीर रक्त विकारों के रोगियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपचार है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में

केवल संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक बोनमरी कार्यक्रम संचालित है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। कुलपति ने बताया कि सरकारी संस्थानों में अंग और रक्त प्रत्यारोपण केंद्रों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने आदित्य बिड़ला कैपिटल फाउंडेशन के केजीएमयू में अत्याधुनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट के लिए 2.75 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए सीएसआर फंड के माध्यम से मांग की। जिस पर फाउंडेशन ने सहमति व्यक्त की। केनकिड्स किड्सकेन, जो बचपन के कैसर के उपचार के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है, इस प्रकल्प में एक तकनीकी सल्लाहदार है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ केजीएमयू में यह अत्याधुनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित होगी।

उत्कृष्ट काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी सम्मानित



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गौधी जयंती के अवसर पर बुधवार को गोमती नगर स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) सभागार में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिसमें डॉ. रोशन जैकब, मंडलायुक्त लखनऊ मंडल ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कर्मचारियों को उत्कृष्ट काम करने के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. मनोज अग्रवाल ने बताया इस मौके

पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक आशीष कुमार वर्मा, डॉ. श्यामा प्रसाद मुक्ती चिकित्सालय में कार्यरत प्रयोगशाला प्राविधिक धीरज पांडे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुडवा की स्टाफ नर्स अंजना दास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकेटी के फार्मासिस्ट, सत्येंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माल के लैब टेक्नीशियन राकेश कुमार को उत्कृष्ट काम के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं।

एकेटीयू में वालीबॉल में कैश 11 बनी विजेता

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का रजत जयंती वर्ष समारोह सात मई 2024 से आठ मई 2025 तक मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति प्रो जेपी पाण्डेय के निर्देशन में इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को वालीबॉल का फाइनल मुकाबला रजिस्ट्रार 11 एवं कैश 11 के बीच हुआ। बेहद रोमांचक हुए इस मैच का नतीजा तीसरे सेट में निकला।

पहला सेट जहां कैश 11 ने जीता तो दूसरे सेट में रजिस्ट्रार 11 की टीम भारी पड़ी। अंत में तीसरे सेट में कैश 11 ने जीत दर्ज कर विजेता बनी। विजेता टीम के कप्तान डॉ अनुज कुमार शर्मा ने सभी खिलाड़ियों बधाई दी। वहीं, कैश 11 की ओर से गौरव राय ने शानदार खेल दिखाया। जबकि रजिस्ट्रार 11 के कप्तान डॉ आरके सिंह और उनकी टीम ने पूरी कोशिश की मगर परिणाम को अपने पक्ष में नहीं कर सकी। मैच रेफरी शशिार द्विवेदी रहे। इस मौके पर खेल संयोजक प्रो ओपी सिंह सहित काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।

अशासकीय महाविद्यालयों के 1124 पद होंगे स्थायी

लखनऊ। शासन स्तर पर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के 1124 पदों को स्थायी कर दिया गया है। इस बाबत शासन स्तर पर विशेष सचिव ने आदेश जारी कर दिये हैं। शासन के इस निर्णय के बाद इन पदों पर तैनात शिक्षकों को काफी राहत मिल गयी है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के 1234 पद सूचित हैं। इनमें से 9 पदों को छोड़कर कुल 1225 पदों में से 1124 अस्थायी पदों को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद इन पदों के पदधारक को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमत्य हों, भी दिये होंगे।

अनुसूचित जाति आयोग के मनोनीत पदाधिकारियों ने शपथ लेकर किया कार्यभार ग्रहण



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, बैजनाथ रावत, उपाध्यक्षों, बेचन राम एवं जीत सिंह खरवार सहित आयोग के अन्य सदस्यों ने गुरुवार को शपथ लेने के बाद कार्यभार ग्रहण किया। समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), असीम अरुण ने गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में नवमनोनीत पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस 19 सदस्यीय आयोग में सदस्य के

समाज कल्याण मंत्री, असीम अरुण ने दिलाई शपथ

रूप में हरेन्द्र जाटव, महिपाल वाल्मिकी, संजय सिंह, नीरज गौतम, नरेन्द्र सिंह खजूरी, तीजाराम, विनय राम, श्रीमती अनीता गौतम, रमेशचन्द्र, मिठाईलाल, उमेश कठेरिया, जितेन्द्र कुमार एवं अनीता कमल ने शपथ ग्रहण किया। तीन सदस्य जिनमें दिनेश भारत, सिंगनारायण सोनकर एवं रमेश कुमार तूफानी शामिल हैं, किर्हीं कारणोंवश शपथ के लिए उपस्थित नहीं हो सके। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के अवसर पर

समाज के उपेक्षित एवं पीड़ित व्यक्तियों को संविधान के अनुसार न्याय दिलाने के लिए करना होगा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग हर प्रकार से आयोग के सहयोग के लिए उपलब्ध है। उपेक्षितों की पीड़ के निराकरण में ही आयोग की सफलता है। आयोग के अध्यक्ष, बैजनाथ रावत ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री ने पीड़ितों को न्याय दिलवाने में काफी मेहनत की है। नवगठित आयोग के पदाधिकारियों इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए दिन-रात मेहनत करेंगे।

डीएम ने किया गांधी जयंती पर प्रतियोगिता का शुभारंभ

प्रतियोगिता में सीएमएस सहित 75 विद्यालयों के 2000 छात्रों ने की हिस्सेदारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर गांधी भवन में बच्चों की निबन्ध लेखन व संगीत एवं लघुनाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में सीएमएस सहित 75 विद्यालयों के 2000 छात्रों द्वारा हिस्सेदारी की गयी। गुरुवार को 33 गांधी स्मारक निधि गांधी भवन लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित महात्मा गांधी की 155 वीं जयंती व पूर्व प्रधान मंत्री स्व० लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दूसरे दिन गांधी भवन लखनऊ में बच्चों की निबन्ध लेखन व संगीत एवं लघुनाटिका प्रतियोगिता का आयोजन किया। निबन्ध लेखन व संगीत एवं लघुनाटिका प्रतियोगिता का शुभारम्भ जिलाधिकारी सूर्य पाल



गंगवार ने दीप प्रज्वल व महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि महात्मा गांधी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गांधी भवन में जो आयोजन हो रहा है आप सब महात्मा गांधी के चित्र बना रहे हैं निबन्ध लिख रहे हैं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहें उसका कूठ अंश अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ने सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चल कर देश को आजादी दिलाई। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में जिलाधिकारी ने

शहर में संयुक्त रूप से डेरियों का सर्वे दोबारा करने का निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डीएम की अध्यक्षता में डेरी विस्थापन पर विधान सभा, विधान परिषद और सांसद के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर चर्चा की गयी। बैठक में सदस्यों द्वारा डेरी विस्थापन को अत्यंत गंभीर मुद्दा बताया गया। जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देशित किया गया कि संयुक्त रूप से डेरियों का सर्वे दोबारा कर लिया जाय जिससे यह ज्ञात हो जाय कि डेरिया सरकारी भूमि पर हैं। गुरुवार को जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार एवं अध्यक्षता में लाल निरंजन स्कूल, द आफ पब्लिक स्कूल, रानीलक्ष्मी गर्ल्स इंटर कालेज, सिटी मास्टेरी स्कूल आदि लगभग 75 स्कूल के 2000 बच्चों ने भाग लिया। राजनाथ सिंह दिवाकर त्रिपाठी और नगर निगम, आवास विकास परिषद और एलडीए के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गयी। जिसमें दिवाकर त्रिपाठी द्वारा बताया गया की डेरी विस्थापन अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, पूर्ण तरीके से कार्ययोजना बनाकर, जगह चिन्हित कर

लखनऊ नगर निगम सीमा से बाहर लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद द्वारा विकसित किया जाय, जहां पशुओं द्वारा जनित गोबर और मूल मूत्र के उचित निस्तारण की व्यवस्था की जाय, डेरियों के विस्थापन से पूर्व नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा बाई लाइज के तहत सार्वजनिक नोटिस की जाय। जो डेरी सार्वजनिक स्थल, पार्क रोड पर संचालित हो रही हैं उनको तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अंतर्गत सार्वजनिक हित और जन स्वास्थ्य की प्राथमिकता में हटाया जा सकता है। इस के लिए पूर्व में डेरी विस्थापन के सम्बन्ध में कैटल कॉलोनी बसाने की कामधेनु नगर योजना, गोकुल और राधा ग्राम योजना की मदद ली जा सकती है जहां पर पशुपालको को लीज पर भूमि सविसिडिज्डरॉर पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही को आभार मानते हुए कार्ययोजना बनायी जा सकती है।

‘चिपको आंदोलन’ के जरिए दिया तनों की सुरक्षा का संदेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत ‘चिपको आंदोलन’ नाटक का 34वें गांधी जयंती नाट्य महोत्सव 2024 के अवसर पर राजेंद्र तिवारी के लेखन एवं निर्देशन में गुरुवार को गांधी भवन प्रेक्षागृह में मंचन किया गया। जिसमें लखनऊ, हरदोई, मुंबई एवं देश के लगभग सभी क्षेत्रों के कलाकार शामिल हुए हैं। यह नाटक वनों की सुरक्षा पर आधारित है। उत्तराखंड के रेनी गांव की महिलाओं द्वारा पर्यावरण एवं वनों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा आंदोलन करके 1973 को एक नया इतिहास रच दिया था। ठेकेदारों द्वारा की जा रही पेड़ों की कटाव रोकने के लिए महिलाओं ने पेड़ काट रहे मजदूरों के सामने जान की परवाह किए बिना पेड़ों से लिपट गई थी और ऐलान किया था कि पेड़ों को काटने से पहले हम सब को काटना पड़ेगा। ऐसा साहस करने वाली महिला के



साथ उस क्षेत्र की बहुत सी महिलाएं एवं पुरुषों ने भी आंदोलन में पुरजोर से समर्थन दिया। जिसके कारण पेड़ कटाव के ठेकेदार को जनता के सामने झुकना पड़ा और पेड़ों की कटाव को रोकना पड़ा। ऐसा अदभुत साहस दिखाने वाले सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा, चंडी प्रसाद भट्ट, धनश्याम रतुरी, धूम सिंह नेगी आदि जैसे साहसी लोगों के आंदोलन को सदा याद रखा जाए इस उद्देश्य से इस नाटक को तैयार किया गया है। इसमें मुख्य कलाकारों में देविका पटेल, परशुराम लोखंडे, संगीता मिश्र,

प्रतीक्षा गुप्ता, काव्या मिश्रा, मोनिका भारती, साकेत राय, दीपक यादव, अरुण बीरो, संतोष बाग, शिवदान नायक, विशाल दुबे, कार्तिक पिल्लई, रंजन देहरी, अभय यादव, नकुल शर्मा, प्रदीप श्रीवास्तव, सूर्य प्रकाश, संतोष बाबुलकर आदि कलाकार शामिल थे। यह कार्यक्रम अश्वनी शुक्ला, अंजना तिवारी, गणेश रावत, अमित तिवारी, ललित पांडेय, निष्ठा तिवारी, राकेश वर्मा, राकेश तिवारी, शामिल रहे। इनके प्रबंधन एवं सहयोग से नाटक का मंचन संपन्न हुआ।

महापौर ने 5 मृतक आश्रितों को दिया नियुक्ति पत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

महापौर द्वारा जलकल विभाग के मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ऐशबाग में पांच मृतकों आश्रितों को महाप्रबंधक की उपस्थिति में नियुक्ति दी गयी। साथ जलकल के दो कर्मियों को सेवानिवृत्त के दौरान उनके देयकों का भुगतान किया गया। गुरुवार को महापौर, नगर निगम लखनऊ के निर्देश पर जलकल विभाग, नगर निगम, ऐशबाग लखनऊ में नई पहल के रूप में सेवाकाल में मृत्यु हुए कर्मचारियों के आश्रितों को जलकल विभाग में मृतक आश्रित के रूप में सेवार्थीजित किये जाने के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वितरण में महापौर सुषमा खर्कवाल एवं महाप्रबंधक, जलकल विभाग ने किया। उपरोक्त के अतिरिक्त माह सितम्बर, 2024 में सेवानिवृत्त हुए 2 कर्मचारियों के विदायी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इनकी



सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान किया गया, जिसका राकेश कुमार पम्पचालक जोन.7 और सरस्वती सफाई कर्मचारी सचिव कार्यालय। महापौर ने सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में रंजीत सिंह, कार्यकारी सहायक, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित हुए।

इन्हें किया गया सम्मानित

- पवन कुमार गौड़, जूनियर फिटर
- अनिकेत प्रजापति, गैंगमैन
- पंकज, गैंगमैन
- प्रेमलता, गैंगमैन
- संजय कुमार पाल, गैंगमैन

सुनवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने बीडीओ दफ्तर में जड़ ताला, नहीं निकला हल

विभिन्न मांगों को लेकर 30 सितंबर से ब्लॉक कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सैकड़ों किसान

संवाददाता। मोहनलालगंज

विभिन्न मांगों को लेकर तीन दिन से ब्लॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के कार्यकर्ताओं ने सुनवाई नहीं होने पर गुरुवार को एडीओ पंचायत और बीडीओ के दफ्तर में ताला लगा दिया। किसानों को समझाने पहुंचे एएसडीएम और एसपी की किसानों से खर्च वसूली कराने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग भी शामिल की है। इसके अतिरिक्त ब्लॉक की कई पंचायतों में नाली व सड़क निर्माण की मांग और पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन डालने के लिए खोदी जा रही गांव की सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं कराए जाने का मुद्दा भी



किसान जोर शोर से उठा रहे हैं। यही नहीं ब्लॉक में उद्यान विभाग की योजनाओं का किसानों को लाभ देने के लिए स्टॉप की तैनाती नहीं होने का मुद्दा भी किसानों ने मांगपत्र में शामिल कर रखा है। भाकियू जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र वर्मा ने बताया बीडीओ एसपी और एएसडीएम समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वार्ता बेनतीजा रही। मांगें पूरी होने तक किसान धरना समाप्त करने के लिए सहमत नहीं हैं। खोखले आशवासन के भरोसे काम नहीं चलेगा। अगली वार्ता तभी होगी जब अधिकारी मांगें पूर्ण कर उसकी सूचना उपलब्ध करा देंगे।

बिलिंग कंपनी की टीम के साथ एक्सइएन ने फील्ड विजिट कर बनवाए बिल

खबर का असर

एनडी के निर्देश पर ऑनग्रिड सोलर कनेक्शन धारकों को गटकने से गिला छुटकारा

संवाददाता। मोहनलालगंज



रीपोर्ट देने के लिए कहा गया है। मोहनलालगंज खण्ड में पीएम सूर्यधर योजना समेत अन्य ऑनग्रिड कनेक्शनधारक उपभोक्ताओं को अब नई मीटर का वीडियो लेकर एसडीओ और एक्सइएन ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पायनियर में गुरुवार को इसे लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद मध्याह्न प्रबंधन ने मामले का सजाण लेकर मातहतों को समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। एमडी के निर्देश पर एक्सइएन श्रवण कुमार सिंह खुद बिलिंग कंपनी की टीम के साथ निकल पड़े। उन्होंने मोहनलालगंज और गौरा में कई ऑनग्रिड सोलर कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के घर

पहुंचकर मीटर रीडरों को बिल बनाना सिखाया। एक्सइएन श्रवण कुमार सिंह ने बताया बिलिंग कंपनी के सॉफ्टवेयर में ऑनग्रिड सोलर कनेक्शन के बिल बनाने का ऑप्शन है। लेकिन जानकारी के अभाव और डर की वजह से मीटर रीडर बिल नहीं बन रहे थे। जिसे लेकर उनके सारे भ्रम दूर कर दिए गए हैं। अब से प्रतिमाह सभी उपभोक्ताओं के बिल बनाए जाएंगे। एक्सइएन ने कहा सभी मीटर रीडर से कहा गया है कि यदि किसी को बिल बनाने में कोई परेशानी आए तो वह नई मीटर का वीडियो लाकर ऑफिस से भी बिल बनवा सकता है। जबकि पूर्व विधायक समेत अन्य बड़े कनेक्शन धारकों की बिलिंग के लिए मीटर सेक्शन को प्रतिमाह नई मीटर की एमआरआई रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। एक्सइएन ने बताया सभी एसडीओ को उपखण्ड वार नियमित बिलिंग कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

ईरान-इस्त्राइल टकराव

चिन्ता का विषय

ईरान-इस्त्राइल टकराव ईरान के हालिया मिसाइल हमलों के कारण गंभीर हो गया है और यह सारी दुनिया की चिन्ता का विषय बन गया है। ईरान द्वारा इस्त्राइल के खिलाफ भारी संख्या में मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में शांति को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इससे क्षेत्र में व्यापक टकराव की आशंका है। मंगलवार रात को ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं जिसे लगभग 10 मिलियन इस्त्राइलियों को 'बम शेल्टरों' में जाने को मजबूर होना पड़ा। इस्त्राइली रक्षा बलों-आईडीएफ ने हमले को नाकाम करने के प्रयास किए। जहां इस्त्राइल के 'आयरन डोम' व 'ऐरो डिफेंस सिस्टम' ने अधिकांश मिसाइलों को बेकार कर दिया, वहीं कुछ मिसाइलें रक्षा आवरण भेदने में सफल रहीं जिनसे मामूली नुकसान हुआ। इस्त्राइली प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतनयाहू ने फौरन इस हमले की निन्दा करते हुए इसे ईरान की 'भारी गलती' बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि तेहरान को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, हालांकि उन्होंने पूर्ण युद्ध की घोषणा नहीं की है। यह ईरान का इस साल अप्रैल में किए हमले के बाद इस्त्राइल के खिलाफ दूसरा मिसाइल हमला है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि यह मिसाइल हमला हाल में हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्ला व हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्याओं का बदला है जिन पर इस्त्राइली सेना ने निशाना लगाया था।



इस मिसाइल हमले पर फौरन अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियायें सामने आईं। अमेरिका ने ईरान को कठोर चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आश्वासन दिया है कि ईरान द्वारा किसी अन्य हमले के खिलाफ संयुक्त सैनिक कार्रवाई का समर्थन किया जाएगा। इस टकराव में अमेरिका के शामिल होने से पहले से ही अस्थिर यह क्षेत्र और अस्थिर हो जाएगा। इससे न केवल इस्त्राइल,

बल्कि क्षेत्र में अमेरिका के सैनिक हितों पर ईरानी बदले की कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही रूस और चीन भी टकराव में शामिल हो सकते हैं। इस बीच पूरे पश्चिम एशिया में मानवीय संकट बढ़ रहा है। लेबनान और गाजा में हजारों-हजार लोग विस्थापित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने से क्षेत्रीय स्थायित्व संकट में है क्योंकि भौगोलिक रूप से टकराव क्षेत्रों के निकट स्थित ईराक और जार्डन भी हिंसा का शिकार हो सकते हैं। विश्व समुदाय इस क्षेत्र में तनाव घटाने की मांग कर रहा है तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेर्रेस ने तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया है। हालांकि, राजनयिक प्रयास जारी हैं, पर स्थिति शांति की संभावना अभी दूर है क्योंकि इस्त्राइल और ईरान दोनों अर्थ टकरावों की तैयारी कर रहे हैं। इससे क्षेत्र और दुनिया में शांति स्थापना का समय बीतता जा रहा है। यदि अमेरिका और पश्चिमी देश युद्ध में ज्यादा संलिप्त होते हैं तो जल्द ही रूस और चीन भी इसमें कूद सकते हैं। वर्तमान स्थिति में तनाव घटाने का दायित्व प्रमुख विश्व शक्तियों का है जिसमें खासकर अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश शामिल हैं। इस परिदृश्य में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि वह तटस्थ देश है और उसकी मित्रता रूस और अमेरिका के साथ ही इस्त्राइल और ईरान के साथ भी है। फिलहाल टकराव क्षेत्रों में शांति स्थापना तथा सैनिक कार्रवाइयों पर अस्थाई विराम लगा कर शांति वार्ताओं के लिए उपयुक्त परिवेश तैयार किया जा सकता है।

लड्डुओं पर राजनीतिक संग्राम

तिरुपति में लड्डुओं के मुद्दे पर पूरी देश में गुस्सा पैदा हुआ। इससे धर्म, राजनीति और विश्वास के बीच नाजुक संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। राजनेताओं को ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए।

कल्याणी शंकर

(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)



तिरुपति में लड्डुओं के प्रसाद में मिलावटी घी प्रयोग करने के मुद्दे पर पूरी देश में गुस्सा पैदा हुआ। इससे धर्म, राजनीति और धार्मिक विश्वास के बीच नाजुक संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा विक्री किए जाने वाले 'श्रीवारी लड्डू' जैसी मिठाई पर उपजे विवाद और संदेह का विगत दिनों में काफी विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति प्रसाद के लड्डुओं में नकली घी के प्रयोग से मामला बहुत गरम हो गया, पर यह यहीं समाप्त होने वाला नहीं है। पिछले सप्ताह इस मामले ने और तूल पकड़ ली और यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हाथ में एक 'राजनीतिक हथियार' के रूप में सामने आ गया। इस हथियार से वे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर हमला बोल रहे हैं।

कांग्रेस और भाजपा जैसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे अपने लाभ के लिए उठाने का प्रयास किया। कुछ लोग इस प्रकरण को एक धार्मिक मुद्दे की तरह देख रहे हैं, जबकि दूसरों का कहना है कि यह व्यापक रूप से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मामला है। आध्यात्मिक नेताओं का कहना है कि लड्डू ईश्वर का भोजन है और देवताओं को मिलावटी लड्डू नहीं चढ़ाए जाने चाहिए। लड्डुओं से जुड़ा विवाद एक प्रकार से राजनीति, धर्म, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता तथा जनता के बीच नाजुक संतुलन को अस्थिर करता लग रहा है। तिरुपति देवस्थानम पर प्रसादम के रूप में प्रयोग होने वाले स्वादिष्ट लड्डू शुद्ध घी, चीनी, इलायची, मेवों, काजू और बेसन से बनाए जाते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की आधुनिक रसोई में लड्डू प्रसादम बनाने के लिए रोज 14 टन गाय का घी प्रयोग किया जाता है।

पहले इनको देवता को अर्पित किया जाता है और इसके बाद भक्तों को ईश्वरीय प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। भक्तों को लड्डू बेच कर हर साल



लगभग 500 करोड़ रुपये की आमदनी होती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री तेलंगु देशम पार्टी-टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने लड्डू विवाद उठा कर अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी पर राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रेड्डी सरकार ने प्रसाद के रूप में मिलावटी लड्डू का प्रयोग होने दिया जिसे बनाने में प्रयोग होने वाले घी में पशु चर्बी मिली थी।

चंद्रबाबू नायडू ने यह विवादास्पद मुद्दा ऐसे दिन उठाया जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर रही थी। टीडीपी केन्द्र सरकार में शासन करने वाली राजग गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हालांकि, तिरुपति के प्रसाद के रूप में लड्डू के प्रयोग पर साठ और सत्तर के दशक में भी लोगों का ध्यान गया था। उस समय लड्डू बनाने में घी के स्थान पर वनस्पति घी-डालडा के प्रयोग पर चिन्ता जताई गई थी। उस समय विवाद के कारण वनस्पति घी का आयात करने वाले जहाजों को अस्वीकार कर दिया गया था और उसके संप्लानों को काली सूची में डाल दिया गया था।

एक अन्य मामले में दो वैष्णव समूहों के बीच भगवान वैंकरेश्वर को तिलक लगाने के मुद्दे पर विवाद पैदा हुआ था। यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय तक गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था कि

दोनों वैष्णव समुदायों को भगवान वैंकरेश्वर को तिलक करने का अधिकार है और वे हर महीने 15-15 दिन तिलक करेंगे। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि टीडीपी ने जून में आंध्र प्रदेश विधानसभा के चुनाव जीते और जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी-वाईएसआरसीपी की भारी पराजय हुई। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद टीडीपी ने लड्डू मुद्दे का इस्तेमाल किया।

चंद्रबाबू नायडू का दावा है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने खर्च घटाने के उपाय के रूप में खराब गुणवत्ता वाला घी खरीदने की अनुमति दी जिससे तिरुमला लड्डू की गुणवत्ता प्रभावित हुई। नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में हिंदू धार्मिक व्यवहारों की अनदेखी की गई। इस संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जगन मोहन रेड्डी तथा उनके पिता व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजेश्वर रेड्डी ईसाई हैं। जगन मोहन रेड्डी ने स्वयं पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिकायत की है कि नायडू उनसे राजनीतिक बदला ले रहे हैं। वाईएसआरसीपी ने नायडू की आलोचना करते हुए शुद्धीकरण समारोह का आयोजन किया। लेकिन पश्चाताप करने के लिए जगन मोहन रेड्डी को मंदिर में

प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। पिछले सप्ताह जब लड्डू विवाद अपने शिखर पर था तब जगन मोहन रेड्डी को दूसरे दलों का समर्थन नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई थीं और उनको आंध्र प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। शर्मिला ने यह मुद्दा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। आंध्र प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री, नायडू के गठबंधन साझेदार तथा लोकप्रिय फिल्म स्टार पवन कल्याण यह मुद्दा धार्मिक स्तर पर उठा रहे हैं।

पवन कल्याण ने खराब घी प्रयोग करने को गंभीर अपराध मानते हुए 11 दिन पश्चाताप किया। जहां नायडू राजनीतिक कार्ड खेल रहे हैं, वहीं पवन कल्याण इसे धार्मिक मुद्दे की तरह प्रयोग कर रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा होनी चाहिए। मीडिया द्वारा आंकड़े प्रकाशित करने तथा कुछ राजनेताओं द्वारा लड्डू की गुणवत्ता पर सवाल उठाने के बाद इस विवाद ने और जोर पकड़ लिया। इस विवाद के कारण देश भर में संतों और भक्तों में भारी गुस्सा पैदा हुआ। आश्चर्य नहीं कि इसमें भाजपा के सहयोगी संगठन विहिप, अयोध्या के संतों तथा अन्य धार्मिक संस्थानों के लोग भी शामिल हुए और उन्होंने पूरे प्रकरण को गंभीर जांच की मांग की। अयोध्या और पुरी जैनाथ के पुजारियों ने अपने यहां प्रयोग

होने वाले प्रसाद को गुणवत्ता जांच के लिए भेजा। लड्डू विवाद के बाद इस मांग ने फिर पकड़ लिया है कि मंदिरों को राज्य-नियंत्रण से मुक्त किया जाए। हालांकि, यह मांग समय-समय पर उठती रही है, पर कोई सरकार देश भर में मौजूद विशाल मंदिरों को अपने नियंत्रण से मुक्त नहीं करना चाहती है।

इस मामले के विधिक पक्ष पर गौर करें तो पता चलेगा कि हिंदू सेना समिति के सुरजीत सिंह यादव ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मुद्दे की विशेष जांच समिति से जांच कराने की मांग की है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने भी इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति गठित की है। केन्द्र ने इस बारे में राज्य सरकार से रिपोर्ट भेजने को कहा है। इस बीच विवाद का केन्द्र रहे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने अपनी छवि को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अनेक प्रयास किए हैं। उसने मंदिर में एक व्यापक शुद्धीकरण अभियान चला कर भक्तों को आश्वासन दिया है कि लड्डू मिलावटी नहीं हैं। उसने लड्डू बनाने में प्रयुक्त घी के संप्लानों पर प्रतिबंध लगा कर कान्टैक राज्य सरकार की संस्था नंदिनी से घी खरीदने का निर्णय किया है। चूंकि लड्डू में मिलावट का मुद्दा अब अदालत पहुंच गया है, इसलिए इसके जल्दी समाधान की उम्मीद नहीं है। इस मुद्दे में नए-नए बिंदु भी सामने आ रहे हैं।

ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ही कुछ अन्य राजनेता भी इस मुद्दे का जल्दी समाधान नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा संवेदनशील मुद्दा नियंत्रण के बाहर भी जा सकता है और अनियंत्रित होने पर यह कानून-व्यवस्था की समस्या भी पैदा कर सकता है। यह मुद्दा जब तक बना रहेगा तब तक धार्मिक भवनायें भड़कने का खतरा भी बना रहेगा। इस विवाद से स्पष्ट है कि राजनीति, भोजन और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनेताओं और धर्म गुरुओं को इस तथ्य पर गौर करना चाहिए कि समाज के विभिन्न हिस्से आध्यात्मिक मामलों को कैसे देखते हैं और उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। विश्वास के राजनीतीकरण करने पर वह संदेह के घेरे में आ जाता है। राजनेताओं को ऐसे भावनात्मक मुद्दों पर सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकरण में हमें प्रतीक्षा करनी और यह देखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला करता है।

बदलते ऊर्जा क्षेत्र में अवसर व चुनौतियां

बांग्लादेश द्वारा बिजली खरीद समझौते पर फिर से बातचीत करने के कारण अदानी समूह खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाता है।



सूर्य सारथी रे (लेखक, वित्तीय पत्रकार हैं)

बाजार की गतिशीलता, विशेष रूप से भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में, व्यापारिक और असंबद्ध क्षमताओं के लिए अद्वितीय अवसर प्रस्तुत करती है। ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त पदचिह्न रखने वाले भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक अदानी समूह के लिए, बांग्लादेश के साथ वर्तमान बिजली खरीद समझौता (पीपीए) एक अवसर और एक संभावित चुनौती दोनों है। बांग्लादेश में पीपीए पर फिर से बातचीत करने की बढ़ती आवाजों के साथ, परिदृश्य बदल रहा है, जो अदानी के लिए जोखिम और लाभ दोनों प्रस्तुत करता है। अदानी और बांग्लादेश के बीच पीपीए की स्थापना लगातार बिजली की कमी और

बढ़ती बिजली की मांग का सामना कर रहे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई थी। इस समझौते के तहत, अदानी ने झारखंड के गोड्डा जिले में एक समर्पित 1,600 मेगावाट बिजली संयंत्र का निर्माण किया, विशेष रूप से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। आवश्यक ट्रांसमिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित 2 बिलियन डॉलर की यह परियोजना जून 2023 में पूरी तरह से चालू हो गई थी और अब यह बांग्लादेश की बेस लोड मांग का लगभग 7-10 प्रतिशत पूरा करती है, खासकर देश के उत्तरी क्षेत्रों में।

बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है। जबकि बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है। जबकि बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है। जबकि बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है।

यह कदम अदानी पारन के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह गोड्डा अडानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है। जबकि बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है।

बकाया है। इस बकाया ऋण के बावजूद, अदानी ने अपनी आपूर्ति जारी रखी है, लेकिन ऋणदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं के प्रति अपने दायित्वों को देखते हुए स्थिति को लगातार अस्थिर पार रहा है। यह बढ़ता हुआ प्राय्य मुद्दा अदानी की क्रेडिट प्रोफाइल को प्रभावित करने की धमकी देता है, जिससे संभावित रूप से इसके संचालन में धन की लागत बढ़ सकती है। एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव में, भारत सरकार ने हाल ही में बिजली निर्यात करने वाले बिजली संयंत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ने की अनुमति दी है।

यह कदम अदानी पारन के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह गोड्डा अडानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है। जबकि बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है। जबकि बांग्लादेशी मीडिया की हालिया आलोचनाओं में आरोप लगाया गया है कि अदानी अत्यधिक दरों पर बिजली बेच रहा है।

यदि बांग्लादेश अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है या पीपीए को समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो

अदानी भारत के भीतर बिक्री पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। इस परिदृश्य को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक कारणों में से एक भारत और बांग्लादेश के बीच बिजली दरों में असमानता है। भारतीय बिजली बाजार में मजबूत आर्थिक विकास से प्रेरित बिजली की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

भारत में बिजली की आपूर्ति को पुनर्निर्देशित करके, अदानी इन उच्च दरों का लाभ उठा सकता है, जिससे लाभप्रदता बढ़ सकती है। हाल के रद्धानों से संकेत मिलता है कि बिजली की कीमतें लंबी अवधि के लिए लगभग 10 किलोवाट प्रति घंटे तक पहुंच गई हैं, कोयला आधारित बिजली की बढ़ती मांग के कारण यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।

बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कोयले की लागत वैश्विक बाजार वित्त उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती है। जबकि गोड्डा संयंत्र आयातित कोयले पर काम करता है, भारत के कोयला भंडार के करीब होने के कारण रसद लागत कम हो जाती है, जिससे अदानी की परिचालन दक्षता में

वृद्धि होती है। इस संदर्भ में, अदानी बांग्लादेश के साथ मौजूदा पीपीए के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के बजाय भारतीय बाजार में अपनी बिजली आपूर्ति को पुनर्निर्देशित करने से काफी लाभान्वित हो सकता है। विनियामक वातावरण।

भारत सरकार के आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से घरेलू बिजली उत्पादकों के लिए अनुकूल वातावरण बना है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल आयात निर्भरता को कम करने और स्थानीय उत्पादन और प्रभावी ढंग से संयोजित करने के लिए अदानी भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों को प्रभावी ढंग से संयोजित करने के लिए अपने संसाधनों का लाभ उठा सकता है। राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनुमान है कि भारत की अधिकतम बिजली मांग वित्त वर्ष 202 में 203 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 27 तक 277 गीगावाट और वित्त वर्ष 32 तक 366 गीगावाट हो जाएगी। इस वृद्धि का अर्थ है कि वित्त वर्ष 32 तक बिजली का 80% है कि वित्त वर्ष 32 तक

क्षमता की आवश्यकता है। गोड्डा संयंत्र में अपनी मौजूदा 1.6 गीगावाट क्षमता के साथ, अदानी इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

जबकि पीपीए को समाप्त करने के संभावित लाभ आकर्षक हैं, ऐसे कदम में निहित जोखिम हैं। एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को तोड़ने से कूटनीतिक परिणाम हो सकते हैं और अदानी की वैश्विक प्रतिष्ठा पर प्रतिबल प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, अगर बांग्लादेश सरकार समझौते पर फिर से बातचीत या उसे समाप्त करने की पहल करती है, तो अदानी खुद को अधिक लाभप्रद स्थिति में पाएगा, जिससे वह पीपीए की बाधाओं के बिना आकर्षक भारतीय बाजार की ओर बढ़ सकेगा। कंपनी को समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को संतुलित करना चाहिए और साथ ही भारत में उभरते बाजार की स्थितियों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त रूप से चुस्त रहना चाहिए, जिससे इसकी दीर्घकालिक वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

हिज्बुल्ला प्रमुख हसन नसरुल्ला की मौत के बाद ईरान और इजरायल के बीच युद्ध के शुरूआत हो चुकी है। दोनों तरफसे बदला लेने की गंभीर चेतावनियां दी जा रही है तथा मिसाइल अटैक शुरू हो चुके हैं। लाल सागर क्षेत्र भारत के लिए माल लाने ले जाने का सबसे सुगम मार्ग था, पर युद्ध के चलते यह मार्ग अब खतरनाक हो गया है। भारत सहित कई देशों को लंबे रास्ते से अपना आयात निर्यात जारी रखना होगा जिससे परिवहन खर्च में भारी वृद्धि हो जाएगी। पेट्रोलियम पदार्थों की कमीत बढ़ने लगी है। खाद्यान्न और अन्य सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं। जैसे-जैसे युद्ध फैल रहा है, वैसे-वैसे युद्धप्रस्त देशों के

साथ-साथ विश्व के अन्य देशों की भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युद्धप्रस्त देशों ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जिससे शांति वार्ता के सभी रास्ते लगभग बंद हो गए हैं। युद्ध के विस्तार लेने वाला इसमें अन्य देशों के शामिल होने की आशंका बनी हुई है। चीन और ईरान ने पिछले साल एक सुरक्षा संधि की थी जिससे चीन और रूस भी ईरान की ओर से युद्ध में शामिल हो सकते हैं। अमेरिका ने इजरायल का साथ देने की घोषणा पहले ही कर दी है। इस कठिन बढ़ने लगी है। खाद्यान्न और अन्य सभी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं। जैसे-जैसे युद्ध फैल रहा है, वैसे-वैसे युद्धप्रस्त देशों के

यहूदी राष्ट्र की एकजुटता

इजरायल और हमास के बीच युद्ध को एक वर्ष होने को है। अब इसमें हिजबुल्ला और ईरान भी कूद पड़े हैं। शायद यह युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया को अपनी चपेट में ले ले। इजरायल यहूदियों का एकमात्र देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 80 लाख है। यह चारों तरफ से इस्लामीक देशों से घिरा हुआ है। संयुक्त राष्ट्रसंघ का सदस्य होने के बावजूद अब भी अनेक इस्लामी संगठन इस्त्राइल को मिटाने की कसमें खाते हैं और ईरान जैसे देश भी इनमें शामिल हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अप्रत्याशित आतंकी हमला किया था जिसमें इजरायल के 1200 निर्दोष नागरिक मारे गये, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और 250 नागरिक बंधक बना लिए गए। यह हिटलर द्वारा किए नरसंहार के बाद इस्त्राइल पर सबसे बड़ा हमला था। अपने अस्तित्व पर संकट देख कर इस्त्राइल की पूरी जनता अपनी सेना और प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतनयाहू के साथ एकजुट हो गई है। इसका कारण यह भी है कि इजरायल को विदेश नीति और सुरक्षा के विषय में विषयी दल भारत की तरह रोड़ा नहीं बनते। यहूदी राष्ट्र की एकजुटता तथा उसकी जनता में देशप्रेम की भावना सारी दुनिया के लिए एक आदर्श है।

- नरेंद्र टोंक, मेरठ

जी-7 बैठक

जी-7 समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान, इटली और जर्मनी शामिल हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जाना हमारे लिए गर्व की बात है। इटली की प्रधानमंत्री जर्जिया मेलेनी ने मोदी को आमंत्रित किया है। अन्य मुद्दों के साथ प्रमुख रूप से इस बैठक में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए उस पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने हेतु दोनों देशों से बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी हमले के बाद इस्त्राइल के प्रधानमंत्री बेन्जामिन नेतनयाहू से बात कर स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है।

स्वच्छता अभियान

सचमुच पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान से भारत बहुत कुछ साफ-सुथरा हुआ तथा गंदगी और कचरे से मुक्त हुआ है। पश्चिम एशिया में बंदूकी हमारी आर्थिक व राजनयिक शक्ति का परिणाम है। जी-7 की आपात बैठक में संभवतः पश्चिम एशिया में युद्ध के विस्तार तथा इसके विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा होगी। उम्मीद है कि जी-7 में शामिल महाशक्तियां व भारत पश्चिम एशिया में युद्धविराम करने तथा दीर्घकालीन शांति के लिए वार्ताओं की स्थिति बनाने में सफल होंगे। यह सारी दुनिया के लिए जरूरी है।

शकुन्ता महेश नेनावा, इंदौर

युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने को पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटरर्शिप योजना आरंभ

नई दिल्ली। सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से बृहस्पतिवार को पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटरर्शिप योजना शुरू की। योजना के तहत इंटरर्शिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रूपए मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें इंटरर्शिप जॉइन करने को लेकर एकबारागी 6,000 रूपए की सहायता दी जाएगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटरर्शिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इस पर 800 करोड़ रूपए का खर्च आने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024–25 के अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार इंटरर्शिप प्रदान करने के लिए एक ब्यापक योजना शुरू करेगी। इसके तहत पांच साल में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में

प्रशिक्षण का अवसर दिया जाएगा। उन्हें वास्तविक रूप से कारोबारी माहौल, विभिन्न कारोबार क्षेत्रों में 12 महीने कामकाज के गुर सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। योजना को ऑनलाइन पोर्टल...डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पीएमइंटरर्शिप डॉट एमएसई डॉट जीओवी डॉट इन... के जरिए लागू किया जाएगा। पोर्टल का विकास कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने किया है। इंटरर्शिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर दिया जाएगा। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। कंपनियां चयनित उम्मीदवार को अतिरिक्त टुर्यंटना बीमा उपलब्ध करा सकती हैं। सूत्रों ने कहा कि पायलट परियोजना दिसंबर के पहले

सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद है। उसके बाद इसे पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का नियम इस योजना में भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से भागीदार कंपनियां इंटरर्शिप के अवसर प्रदान कर सकती हैं। पायलट परियोजना के लिए शीर्ष कंपनियों की पहचान पिछले तीन साल में उनके सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व) व्यव के औसत के आधार पर की गई है। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण चाहते हैं, वे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते है। इंटरर्शिप एक साल के लिए होगी। कोई भी अन्य कंपनीबैंकावित्तीय संस्थान मंत्रालय की मंजूरी से इस योजना में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षुओं को प्रति माह 5,000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुल रशि में से

4,500 रूपए सरकार सीधे चयनित उम्मीदवार के बैंक खाते में डालेगी जबकि 500 रूपए कंपनी अपने सीएसआर कोष से भुगतान करेगी। योजना के तहत प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण से जुड़ा खर्च कंपनी अपने सीएसआर कोष से उठाएगी। पूर्णकालिक नौकरी और पढ़ाई नहीं कर रहे 21 साल से 24 साल के युवा इसके लिए पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइनदूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं। पात्रता मानदंड के बारे में सूत्रों ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल से उत्तीर्ण की है, आईटीआई का प्रमाण पत्र है, पॉलिटेक्निक संस्थान से डिप्लोमा है, या बीए, बी.एससी, बी.कॉम, बीसीए, बीबीए, बी.फ़ार्मा जैसी डिग्री के साथ स्नातक हैं, वे इसके लिए पात्र होंगे।

बौद्ध धर्म से जुड़े नए तथ्यों को जानने में सहायक होगा बौध्

अध्ययन केंद्र: उपमुख्यमंत्री
ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने बृहस्पतिवार को कहा कि रजवीव गांधी वि्वि (आरजीयू) में बनने वाले बौद्ध अध्ययन केंद्र से बौद्ध धर्म का शाश्वत दर्शन, सिद्धांतों का अध्ययन करने और इससे जुड़े नए तथ्यों को जानने में मदद मिलेगी। मीन ने छात्र गतिविधि केंद्र का उद्घाटन और बौद्ध अध्ययन केंद्र की आधारशिला रखते हुए कहा कि महायान और हीनयान दोनों संप्रदायों के कई बौद्ध छात्र और विद्वान वर्तमान में अध्ययन के लिए म्यांमार, थाईलैंड और बोधगया स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जाते हैं। इस एन केंद्र के जरिए छात्र स्थानीय स्तर पर बौद्ध धर्म का अध्ययन कर सकेंगे और नई-नई बातें जान सकेंगे। निवर्तमान कुलपति प्रोफ़ेसर साकेत कुशवाहा के कार्यकाल के दौरान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मीन ने कहा कि पिछले छह वर्षों में शैक्षणिक विभागों की संख्या दोगुनी हो गई है।

आतंकवादियों के इंक्रिटेड हैडसेट का जल्द तोड़ निकाल लेगी सेना: लेफिटनेंट जनरल राजीव

श्रीनगर। कश्मीर घाटी में सेना के शीर्ष अधिकारी लेफिटनेंट जनरल राजीव घई ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेना जल्द ही जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इंक्रिटेड हैडसेट का तोड़ निकालने में सक्षम होगी। लेफिटनेंट जनरल घई ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए माना कि आतंकवादियों के बीच संचार आतंकवादी समूहों को गोपनीयता प्रदान कर रहा है उन्होंने आक्षानन दिया कि इसका तोड़ निकालने का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा, आतंकवादियों के बीच संचार में इंक्रिप्शन की विभिन्न परतें हैं और वर्तमान में यह उन्हें हथ गोपनीयता प्रदान कर रहा है जो वे चाहते हैं। लेफिटनेंट जनरल घई ने बारे के कमांडर के रूप में अंतिम बार संवाददाताओं को संबोधित करते कहा, लेकिन मैं आपको भरोसा

दिलाता हूं कि इस संबंध में काम जारी है और जल्द ही हम उस इंक्रिप्शन का तोड़ निकालने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इससे आतंकवादी नेटवर्क पर और भी अधिक असर पड़ेगा। घई जल्द ही सैन्य संचालन के महानिदेशक का पदभार संभालेंगे।

इज़राइल-लेबनान संघर्ष में मोबाइल फोन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा, जब भी दुनिया भर में किसी भी सैन्य बल द्वारा कोई नया तरीका अपनाया जाता है तो हम हमेशा सबक सीखने के लिए उस पर ध्यान देते हैं ताकि हम अपने लिए प्रासंगिक चीजों को शामिल कर सकें और अपनी सेना व सशस्त्र बलों को उसी के अनुसार तैयार कर सकें। उन्होंने कहा, पश्चिम एशिया में जो कुछ हम देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से एक नया चलन है और जिस तरह से

यह सामने आ रहा है, वह काफी अनोखा है। इसलिए हम निश्चित रूप से इसका विश्लेषण करेंगे और इस बारे में निकफं निकालेंगे कि क्या प्रासंगिक है तथा यह हमें कैसे प्रभावित कर सकता है।

ये अल्ट्रा हैडसेट कश्मीर घाटी में कुछ मुठभेड़ों से बरगम किए गए थे। पाकिस्तानी सेना के लिए विशेष रूप से चीनी कंपनियों द्वारा निर्मित इन विशेष हैडसेट को पिछले साल 17-18 जुलाई की मध्यरात्रि में जम्मू क्षेत्र के पुंछ जिले के सुनक्रेट के सिंदराह शीप क्षेत्र में और इस साल 26 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर के बारगमूला जिले के सोपोर के चेक मोहल्ला नीोपा इलाके में मुठभेड़ के बाद जब किया गया था। डिवाइस संदेश प्रसारण और रिसेप्शन के लिए रैंडियो तरंगों पर काम करता है। प्रत्येक अल्ट्रा सेट सीमा पर स्थित एक नियंत्रण स्टेशन से जुड़ा होता है और दो अल्ट्रा सेट एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते हैं।

जाति आधारित भेदभाव केखिलाफ लड़ाई रतौरत नहीं जीती जा सकती: उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे रतौरत जीता जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास, समर्पण और असमानता को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंडों का सामना करने तथा उन्हें चुनौती देने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई का प्रमाण है और जाति के व्यापक प्रभाव को देखते हुए सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उच्चतम न्यायालय ने करीब 11 राश्यों की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति के आधार पर काम के बंटवारे और कैंदियों को अलग-अलग वार्ड में रखने के चलन की निंदा की। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि संविधान में मौलिक गलतियों के स्थान पर मौलिक अधिकारों को स्थापित करने का प्रावधान है।

संविधान के प्रावधानों के माध्यम से इसने सदियों पुरानी जाति-आधारित पदानुक्रमित

सामाजिक व्यवस्था को हटा दिया, जो व्यक्तिगत समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देती थी। शीर्ष अदालत ने कहा, जाति-आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे रतौरत जीता जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास, समर्पण और असमानता को कायम रखने वाले सामाजिक मानदंडों का सामना करने और उन्हें चुनौती देने की इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। पीठ ने कहा, जाति-आधारित भेदभाव की कृथाओं का सामना करने पर इस न्यायालय को सक्रिय रख अपनाना चाहिए। मौजूदा याचिका पर विचार करके यह न्यायालय जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कह रहा।

संघर्ष में अपना योगदान दे रहा है। पीठ ने कहा कि आधुनिक समय में आपराधिक कानूनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करें। आपराधिक कानूनों को औपनिवेशिक या पूर्व-औपनिवेशिक दर्शन का समर्थन नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, संविधान लागू होने के बाद समाज में, सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

किसानों का दो घंटे का रेल रोको आंदोलन, ट्रेन सेवा प्रभावित

होशियारपुर, लुधियाना। लखीमपुर खीरी कांड (2021) के पीड़ितों को न्याय दिलाने समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में बृहस्पतिवार को किसानों ने दो घंटे के रेल रोको विरोध प्रदर्शन के तहत रेल की पटरियों पर धरना दिया, जिससे पूरे पंजाब में कई ट्रेन की आवाजाही प्रभावित हुई। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चों की ओर से आयोजित यह विरोध प्रदर्शन राज्य में 33 स्थानों पर मध्याह्न साढ़े 12 बजे शुरू हुआ। यह लखीमपुर खीरी में 2021 में तीन कृषि कृथाओं का सामना करने पर इस न्यायालय को सक्रिय रख अपनाना चाहिए। मौजूदा याचिका पर विचार करके यह न्यायालय जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कह रहा।

संघर्ष में अपना योगदान दे रहा है। पीठ ने कहा कि आधुनिक समय में आपराधिक कानूनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करें। आपराधिक कानूनों को औपनिवेशिक या पूर्व-औपनिवेशिक दर्शन का समर्थन नहीं करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, संविधान लागू होने के बाद समाज में, सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो, इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।

नगरी एक्सप्रेस, दुर्ग-जम्मू तवी स्पेशल, अमृतसर-जयनगर शहीद एक्सप्रेस, अमृतसर-अजमेर एक्सप्रेस, पुणे-जम्मू तवी झेलम एक्सप्रेस, जामनगर-माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस और जम्मू तवी-अहमदाबाद एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, ऋण माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और लखीमपुर खीरी की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने की मांग की। अमृतसर में मनावाला रेलवे स्टेशन के पास किसानों के अमृतसर-दिल्ली रेल की पटरियों पर बैठ जाने से दोनों शहरों के बीच चलने वाली कई ट्रेन का मार्ग बदलना पड़ा। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने लखीमपुर रह या फिर किसी भी ट्रेन का मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन केवल उन्हीं स्टेशनों पर रोकी गई, जहां यात्रियों को आसानी से भोजन और अन्य सुविधाएं मिल सकती थीं। जिन ट्रेन को रोका गया उन्में लुधियाना-फिरोजपुर कैंट एक्सप्रेस, मांग पूरी करने के लिए दबाव बनाने में

उद्देश्य से एसकेएम और केएमएम किसानों के दिल्ली चलो मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान 13 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा उनके मार्च को रोके जाने के बाद से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी सीमा पर बैठे हुए हैं। होशियारपुर में भारतीय किसान यूनियन (दोआबा) के राज्य उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा मंडियाला गांव में रेलवे क्रासिंग के पास पटरियों पर धरना दिए जाने से होशियारपुर से जालंधर जाने वाली एक यात्रा ट्रेन को नसराला रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। किसान मजदूर हितकारी सभा के सदस्यों ने जालंधर जिले के भंगाला में अनाज मंडी से रेलवे स्टेशन तक मार्च किया और जालंधर-जम्मू रेल खण्ड पर धरना देने से पठारकोट जाने वाली एक मालगाडी के मुकेरियां रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़ा।

जिलाध्यक्ष परमजीत सिंह भुल्ला के नेतृत्व में किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्यों ने टांडा रेलवे स्टेशन पर रेल पटरी पर धरना दिया, जबकि गन्ना संघर्ष समिति के सदस्यों ने दसूहा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर धरना दिया। लुधियाना में किसानों ने साहेनवाल और फिल्लौर रेलवे स्टेशनों पर रेल पटरियों पर धरना दिया।

एडर मार्शल एसपी धारकट ने वायुसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला

नई दिल्ली। एयर मार्शल एस पी धारकर ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया। वह एयर चीफ मार्शल अमल प्रीत सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख बने थे। लड़ाकू विमानों के कुशल पायलट धारकर को 3,600 घंटे की उड़ान का अनुभव है। एयर मार्शल धारकर ने विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान और प्रशिक्षण विमान उड़ाए हैं और मिग-27 स्क्राइज को क्रमान संभाली है। अनुभवी योग्य उड़ान प्रशिक्षक, लड़ाकू स्ट्राइक लीडर और इंट्रस्ट्रीट येंडिंग प्रशिक्षक हैं। 1985 में फ़ाइटर स्टीम में कमीशन प्राप्त करने वाले धारकर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, एनडीए, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और अमेरिकी एयर वार कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। प्रंटालान लुड्कू इकाई की कमान संभाली और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के पहले महानिदेशक के रूप में कार्य किया। एयर मार्शल धारकर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभालने से पहले पूर्वी वायुकमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ रूप में कार्यरत थे।

पेज 1 का शेष वैवाहिक...

2022 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर विभाजित फैसला सुनाया कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक अपराध माना जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद यह मामला उसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

दिल्ली पुलिस...

रिटनं मिल। हालांकि, जुलाई से ऐप ने तकनीकी गड़बड़ियों, कानूनी मुद्दों, जीएसटी मुद्दों आदि का हवाला देते हुए भुगतान रोक दिया। डीसीपी तिवारी ने कहा, कथित कंपनियां उत्तर प्रदेश के नोड्डा में अपना कार्यालय बंद करने के बाद गायब हो गईं। पुलिस ने कहा कि मास्टरमाइंड शिराम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके चार अलग-अलग बैंक खातों से 18 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। 16 अगस्त को, पुलिस को इंटील्लिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस में मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ 29 पीठियों से शिकायतें मिलीं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि

जम्मू कश्मीर चुनाव में 63.88% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया

भाषा। नई दिल्ली

जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 69.69 प्रतिशत मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुल 63.88 प्रतिशत लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कुल मिलाकर मतदान केंद्रों पर 63.88 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि लोकसभा चुनाव में 58.58 प्रतिशत लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। निर्वाचन आयोग (ईसी) ने बताया कि एक अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश में 40 सीटों पर मतदान के दौरान तीसरे चरण में पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 69.37 प्रतिशत रहा, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 70.02 रहा। आयोग ने बताया कि तीसरे चरण में तीसरे लिंग के करीब 44

प्रतिशत मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल हुए। इसने बताया कि कुल मतदान 63.88 प्रतिशत रहा, जिसमें पुरुषों की भागीदारी 64.68 प्रतिशत रही। आयोग ने कहा कि राज्य की 63.04 प्रतिशत महिलाओं ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। तीसरे लिंग के मतदाताओं का मतदान फीसद 38.24 रहा। आयोग ने बताया कि डाक से प्राप्त हुए मतपत्रों की गिनती के बाद मतदान के अंतिम आंकड़ों का पता चल पाएगा। आयोग ने कहा कि डाक मतपत्रों में सेवारत, अनुपस्थित मतदाताओं (85 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाओं के अंग) और चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को दिए गए डाक मतपत्र शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि स्थापित दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राप्त होने वाले ऐसे डाक मतपत्रों का दैनिक विवरण सभी उम्मीदवारों को दिया जाता है।

आयोजन समिति में मुस्लिम व्यक्ति के शामिल होने पर विवाद के बाद इंदौर में गरबा कार्यक्रम रद्द

इंदौर (मध्यप्रदेश)। इंदौर में एक गरबा कार्यक्रम की आयोजन समिति में एक मुस्लिम व्यक्ति के शामिल होने को लेकर बजरंग दल द्वारा पुलिस के सामने आपत्ति जताए जाने के बाद बृहस्पतिवार को यह 10 दिवसीय कार्यक्रम ऐन मौके पर रद्द कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता राजेश बिंजने ने बताया कि बजरंग दल ने भंवरकुआं पुलिस को सौंपे ज्ञापन में कहा था कि गणेश नगर में कथित तौर पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और अश्लीलता फैलाने के मकसद से गरबा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बजरंग दल ने पुलिस से मांग की थी कि फिरोज खान नामक व्यक्ति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए।

लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठन यह दावा करने के लिए करते हैं कि मुस्लिम पुरुष अन्य धर्मों की महिलाओं को इस्लाम में

धर्मांतरित करने के लिए लुभाते हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पुष्टि की कि पुलिस को गणेश नगर में प्रस्तावित गरबा कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल का ज्ञापन मिला है। उन्होंने बताया कि आयोजकों ने अब तक इस गरबा कार्यक्रम को अनुमति के लिए पुलिस को कितना पत्र नहीं किया है। दंडोतिया ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस गरबा कार्यक्रम को अनुमति के लिए पुलिस से संपर्क करेगा, तो वैधानिक कदम उठाए जाएंगे।

उधर, गणेश नगर के शिखर गरबा मंडल के कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल फिरोज खान ने दावा किया कि पुलिस ने उनके संगठन को 10 दिवसीय गरबा कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उस जमीन के मालिक पर अनुचित दबावे बनाया जिस जगह गरबा होना था, नतीजतन उन्हें यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। खान ने कहा, हम पिछले

36 सालों से गणेश नगर में गरबा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं बचपन से गरबा पंडाल में सेवा करता आ रहा हूँ। लेकिन पहली बार कुछ लोगों को मेरे मुस्लिम होने के कारण इस गरबा कार्यक्रम को लेकर समस्या हुई है।

उन्होंने भावुक होते हुए कहा, जिन लोगों को यह समस्या हुई है, मेरा उनसे निवेदन है कि वह गरबा कार्यक्रम आयोजित होने दें ताकि कई दिनों से तैयारी कर रही 250 से 300 महिलाएं गरबा कर सकें। अगर लोगों को मेरे नाम से समस्या है, तो मैं गरबा पंडाल में कदम तक नहीं रखूंगा। खान ने कहा कि वह अपने मोहल्ले के इकलौते मुस्लिम हैं और इंद के साथ दोपावली भी मनाते हैं। शिखर गरबा मंडल का कार्यक्रम रद्द होने से आयोजक निराश हैं। इस गरबा मंडल की नींव रखने वाले लोगों में शामिल दीपक हांडिया ने कहा, हमारा गरबा पंडाल सज गया था।

पश्चिम एशिया में तनाव के चलते लुढ़का शेयर बाजार

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई यह 1,832.27 अंक टूटकर 82,434.02 अंक पर आ गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निप्प्टी की 546.80 अंक यानी 2.12 प्रतिशत का गोटा लगाते हुए 25,250.10 अंक पर आ गया। संसेक्स की कंपनियों में से लार्सन एंड टुबो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, एशियन पेट्र्स, टाटा मोटर्स, बजाज प्लहन्स, मार्सैट, बजाज फिनसर्व, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, अदाणी पोर्ट्स और एचडीएफसी बैंक में खासी गिरावट दर्ज की गई। बाजार की चौरफ गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसेक्स की 30 कंपनियों में से अकेले जेएसएलव्यू स्टील ही बढ़त लेने में सफल रही। जियोजीत फाइनॅशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, इजराइल पर ईान की तर्फ

से बैलिस्टिक मिसाइल दगो जाने के बाद घरेलू बाजारों में तेज गिरावट आई। दरअसल, अब इजराइल की तरफ से तेल उत्पादक ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने की आशंका बढ़ गई है जो इस संघर्ष को बड़ा रूप दे सकता है। नायर ने कहा, वायदा एवं विकल्प खंड के लिए सीबी ने नू नियमों ने भी बाजार में सौंदों की संख्या कम होने से जुड़ी चिंता बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ चीन में बाजार का मूल्यवत आकर्षक होने से विदेशी निवेशकों ने अब अपनी पूंजी का रख उधर मोड़ दिया है जिससे भारतीय शेयरों पर दबाव बढ़ गया है। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,579.35 करोड़ रूपए के शेयरों की

शुद्ध बिकवाली की थी। व्यापक बाजार में बीएसई मिड्केय सूचकांक 2.27% की बढ़ी गिरावट पर रहा।

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय से याचिका अपने पास स्थानांतरित की

भाषा | नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के कोयंबटूर में आध्यात्मिक गुरु जगजी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन आश्रम में दो महिलाओं को कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने के मामले की पुलिस जांच पर प्रभावी ढंग से रोक लगा दी। उच्चतम न्यायालय ने उस व्यक्ति द्वारा उच्च न्यायालय में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया, जिसने आरोप लगाया था कि उसकी दो बेटियों को ईशा फाउंडेशन के परिसर में बंधक बनाकर रखा गया है। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया कि वह मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के अनुपालन में आगे कार्रवाई न करे जिसमें पुलिस से आश्रम में दो महिलाओं को कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने संबंधी मामले की जांच करने को कहा गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी लापता व्यक्ति या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने के निर्देश देने का अनुरोध करते हुए दायर की जाती है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, आप इस तरह के प्रतिष्ठान में सेना या पुलिस को प्रवेश नहीं दे सकते। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. प्रसादवाला और न्यायमूर्ति मनोज



ईशा फाउंडेशन विवाद

मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि पुलिस मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष वस्तु-स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करेगी। ईशा फाउंडेशन ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटया, जिसमें कोयंबटूर पुलिस को निर्देश दिया गया था कि वह उसके खिलाफ दर्ज सभी मामलों का विवरण एकत्र करे और आगे विचार के लिए उन्हें अदालत के समक्ष पेश करे। ईशा फाउंडेशन ने एक

वयान में कहा, हम इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करते हैं। क्योंकि मामला न्यायालय में विचारार्थीन है, इसलिए हम इस पर और कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। फाउंडेशन की ओर से विरुद्ध अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया और कहा कि लगभग 150 पुलिस अधिकारियों ने फाउंडेशन के आश्रम पर छापेमारी की है और हर कोने की जांच कर रहे हैं। पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए

दोनों महिलाओं से बातचीत की। दोनों महिलाओं ने अदालत को बताया है कि वे स्वेच्छा से फाउंडेशन में रह रही हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने दोनों महिलाओं के पिता को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे दी। पीठ ने कहा, पुलिस 30 सितंबर, 2024 के आदेश के पैग चार में जारी निर्देशों के अनुपालन में इस अदालत में वस्तु-स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा कोई और कार्रवाई नहीं करेगी। इसने कहा, वस्तु-स्थिति पर रिपोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दाखिल करने का निर्देश दिया था, इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 18 अक्टूबर तय की। पीठ ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों महिलाओं ने बताया कि वे आश्रम से जुड़ी थीं। इसने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि उनकी वर्तमान आयु क्रमशः 42 और 39 वर्ष है। पीठ ने कहा कि दोनों महिलाओं ने कहा है कि वे आश्रम से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्होंने समय-समय पर ऐसा किया है और उनके माता-पिता भी उनसे मिलने के लिए वहां आते रहे हैं। इसने कहा कि दोनों व्यक्तियों में से एक ने बताया है कि उन्होंने हैदराबाद में आयोजित मैराथन में भी भाग लिया था। उच्चतम न्यायालय ने

इस बात पर गौर किया कि उसके समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि दोनों व्यक्तियों की मां ने लगभग आठ वर्ष पहले ऐसी ही याचिका दायर की थी, जिसमें पिता भी उपस्थित हुए थे। न्यायालय ने कहा कि फाउंडेशन के वकील के अनुसार इन तथ्यों के आधार पर, विशेष रूप से दोनों महिलाओं की आयु, परिपक्वता और इच्छा को ध्यान में रखते हुए दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। पीठ ने यह भी कहा कि फाउंडेशन के वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय के समक्ष बातचीत के दौरान दोनों महिलाओं ने कहा था कि वे स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के आश्रम में रह रही हैं। पीठ ने कहा, सुनवाई के दौरान हमारा विचार था कि इस अदालत के लिए दोनों संबंधित व्यक्तियों से बातचीत करना उचित होगा और ऐसा हमने कक्ष में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान किया है। पीठ को बताया गया कि दोनों महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में उपस्थित थीं। पीठ ने खुली अदालत में एक महिला से संक्षिप्त बातचीत की और पूछा, क्या आप इस तथ्य से अवगत हैं कि आपके पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है? महिला ने जवाब दिया, हां। हम इसी मामले में उच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे और हमने बताया था कि हम अपनी इच्छा से ईशा योग केंद्र में हैं।



राम मंदिर के शिखर का निर्माण हुआ शुरू, चार माह में पूरा होने की उम्मीद

अयोध्या। (भाषा) अयोध्या में राम मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य बृहस्पतिवार को शुरू हो गया। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नूपेंद्र मिश्र ने कहा कि 161 फुट ऊंचे राम मंदिर के शिखर का निर्माण अगले चार महीने में पूरा होने की उम्मीद है। मिश्र ने एक वयान में कहा कि मंदिर के शिखर के निर्माण की शुरुआत के साथ ही परिसर में सात ऋषियों को समर्पित सात मंदिरों के निर्माण में भी तेजी आई है और इनके भी अगले चार महीने में बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में तेजी लाने के लिए बृहस्पतिवार से तीन दिवसीय समीक्षा बैठक की योजना बनाई गई है जिसमें मजदूरों की कमी होने पर उनकी संख्या बढ़ाने के तरीकों और जरूरत पड़ने पर तकनीकी टीम को

विस्तार देने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की गई थी। नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अयोध्या की विवादित जमीन को राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया था। वहीं, शीर्ष अदालत ने सरकार को सुनी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए किसी अन्य स्थान पर पांच एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया था।

सावरकर पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी को भाजपा ने धारणपूर्ण बताया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के बारे में कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि जिस पार्टी के किसी भी नेता ने एक दिन के लिए भी कालापानी की सजा नहीं झेली, वह उस व्यक्ति का अपमान कर रही है जिसे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सेतुलुर जेल में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि सावरकर मांस खाया करते थे और वह गौ वध के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने बुधवार को कहा, सावरकर एक चितपावन ब्राह्मण थे और वह मांस खाया करते थे। वह एक मांसाहारी व्यक्ति थे तथा गौ वध के खिलाफ नहीं थे। इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर

अमरोहा के रेडियो मैन राम सिंह बौद्ध ने बेजोड़ संग्रह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाई जगह



अमरोहा। (भाषा) उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी रेडियो मैन के नाम से मशहूर राम सिंह बौद्ध ने 1257 रेडियो सेट के बेजोड़ संग्रह की बदौलत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपनी वेबसाइट पर बताया, रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह 1,257 रेडियो है जिसे 13 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के गजौरेला में राम सिंह बौद्ध (भारत) ने तैयार किया है। वेबसाइट के मुताबिक राम को अपना रेडियो संग्रह शुरू करने की प्रेरणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित रेडियो कार्यक्रमों मन की बात को सुनने के बाद मिली। अड़सठ वर्षीय राम सिंह बौद्ध उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजौरेला क्षेत्र के नैपुग गांव के निवासी हैं। अपने पास 1257 अनेखे रेडियो संग्रहित करने पर उनका नाम 26 सितंबर 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बौद्ध ने पीटीआई-भाषा को बताया, 18 फरवरी 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम गजौरेला स्थित नैपुग संग्रहालय आई थी, जहां विभिन्न प्रकार के 1400 रेडियो के संग्रह में से 1257 का चयन किया गया। इसके बाद 26 सितंबर 2024 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज किया गया और 27 सितंबर को वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड किया गया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित संग्रहालय को 137 रेडियो उपहार स्वरूप दिए गए हैं। बौद्ध ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर आकाशवाणी में रेडियो संग्रहालय बनाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बौद्ध की

प्रशंसा करते हुए लिखा कि यह संग्रहालय रेडियो प्रेमियों की विरासत का संरक्षण है जो आने वाली पीढ़ियों को रेडियो की विकास यात्रा से परिचित कराएगा। इससे पहले, 27 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में अमरोहा जिले के रेडियो मैन राम सिंह बौद्ध की रेडियो के प्रति प्रेम और संग्रहालय के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की थी। बौद्ध ने कहा कि मन की बात में जिक्र होने के बाद रेडियो संग्रह में उनकी रुचि और बढ़ गई। उन्होंने बताया कि करीब 25 लाख रुपए की अनुमानित कीमत वाले इस अनूठे संग्रहालय में रेडियो के अलावा अन्य दुर्लभ वस्तुएं भी हैं। इनमें सेवानिवृत्त होने के बाद वह अपना ज्यादातर समय रेडियो के साथ बिताते हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें जीवन भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उन्हें शादी में रेडियो तोहफे में नहीं मिला। बौध ने बताया कि बुध, मर्फी और फिलिप्स जैसी नामी कम्पनियों के अलावा उनके संग्रहालय में सोनी और पैनासोनिक के रेडियो सबसे ज्यादा संख्या में हैं। इनमें सबसे कीमती रेडियो 1920 में बना यूएस आर्मी रेडियो है जिसकी कीमत 20 हजार रुपए है। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा रेडियो जर्मन ग्रांड ड्रॉ लिंक कंपनी का है जिसकी लंबाई डेढ़ मीटर है जबकि सबसे छोटा रेडियो सिर्फ एक इंच का है। इस तरह संग्रहालय में करीब 4,000 रेडियो मौजूद हैं। रेडियो के अलावा बौद्ध के संग्रहालय में अनेक पुरानी चीजें भी मौजूद हैं।

भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताकर खारिज किया

नई दिल्ली। (भाषा) भारत ने बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) की रिपोर्ट को खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक एजेंडा वाला पक्षपाती संगठन करार दिया। भारत ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया। यूएससीआईआरएफ वैश्विक स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की निगरानी करता है। यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत की आलोचना की है। इसने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग से यह सिफारिश भी की है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में भारत को विशेष चिंता वाला देश (कंट्री ऑफ पर्टीकुलर कंसर्न या सीपीसी) घोषित करे। विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि यूएससीआईआरएफ को अपने समय का उपयोग अमेरिका में मानवाधिकारों के मुद्दे से निपटने में अधिक उत्पादक तरीके से करना चाहिए। इस रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन को



लेकर भारत की आलोचना की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के बारे में हमारे विचार सर्वविदित हैं। यह राजनीतिक एजेंडा वाला एक पक्षपाती संगठन है। उन्होंने कहा, यह तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना और भारत के बारे में एक मकसद से गढ़े गए विमर्श को बढ़ावा देना जारी रखता है। हम इस दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट को खारिज करते हैं जो केवल यूएससीआईआरएफ को और बदनमा

के बीच झड़पों का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि महीनों से चल रही हिंसा के परिणामस्वरूप हजारों घर नष्ट हो गए हैं। यूएससीआईआरएफ द्विदलीय अमेरिकी संघ को एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और संसद से नीतिगत सिफारिशें करती है और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखती है। यूएससीआईआरएफ ने कहा, यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि किस प्रकार 2024 के दौरान सतर्कता समूहों द्वारा व्यक्तियों की हत्या की गई, उन्हें पीटा गया और उनकी हत्या की गई, धार्मिक नेताओं को मरमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और घरों तथा पूजा स्थलों को ध्वस्त किया गया। इसमें कहा गया है कि घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन हैं। इसमें कहा गया है कि पिछली मनामोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के समय से ही भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए यूएससीआईआरएफ सदस्यों को देश में आने के लिए लगातार वीजा देने से इनकार किया है।

बलात्कार के आरोपी सपा नेता के खिलाफ अब धोखाधड़ी का मामला

अयोध्या। (भाषा) अयोध्या जिले में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार के आरोप का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुईद खान के खिलाफ एक बैंक को गलत जानकारी देने के आरोप में बृहस्पतिवार को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने यहां बताया कि पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक श्रीप्रकाश ने मुईद पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक की शाखा मुईद की ध्वस्त की चुकी इमारत में बैंक की शाखा थी और 22 अगस्त को धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के आधार पर मुईद पर धोखाधड़ी का आरोप है कि करीब तीन करोड़ की कीमत वाले और चार हजार वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को तालाब और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से बनाया गया था।

पड़। अरुण पुलिस अधीक्षक (शहर) मधुवन कुमार सिंह ने कहा, इस मामले में पूरा कलेंडर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और कार्रवाई कावांई की जा रही है। मुईद खान पर पहले से ही एक नाबालिग लड़की से सामूहिक बलात्कार का आरोप है और हाल ही में उसके खिलाफ गैंगस्टर कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बलात्कार मामले में मुईद का नौकर राजू भी आरोपी है। जुलाई में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने मुईद के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। सबसे पहले कोर्ट ने मुईद को 14 दिनों के लिए जमानत पर छोड़ा और साक्ष्य के आधार पर मुईद को बुलाबोला के शाखा को बलबोला से गिराया जाना था लेकिन कॉम्प्लेक्स में बैंक शाखा होने के कारण ऐसा नहीं किया गया था। इसके बाद बैंक को खाली करने का नोटिस दिया गया था। शाखा के स्थानांतरित होने के बाद 22 अगस्त को शाखा को बलबोला से ध्वस्त कर दिया गया था। प्रशासन का आरोप है कि करीब तीन करोड़ की कीमत वाले और चार हजार वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को तालाब और सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से बनाया गया था।

भेदभाव वाले नियम हट गए

सुप्रीम कोर्ट ने करीब 11 राज्यों की जेल नियमावली के जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को करीब 11 राज्यों की जेल नियमावली के जाति-आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया और साथ ही काम के बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के आधार पर अलग-अलग वार्ड में रखने की प्रथा को निलंबित करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वे इसे तीन महीने बाद 'जेलों के अंदर भेदभाव के संबंध में' शीर्षक के साथ सूचीबद्ध करें। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जर्मन वार्ड के आधार पर चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों में कैदियों की पहचान के आधार पर जेलों के अंदर शारीरिक श्रम, बेरकों का विभाजन किया गया है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, बांग्ला समेत पांच भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मंजूरी दी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्वाव ने कहा, यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजन स्वयं के हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने, हमारी विरासत पर गर्व करने और सभी भारतीय भाषाओं तथा हमारी सभ्यता विरासत पर गर्व करने के इच्छुक है। सावरकर ने कहा कि शास्त्रीय भाषाएं भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की संरक्षण के लिए काम करती हैं, तथा परंपरागत साहित्य और सांस्कृतिक साधन को संरक्षित करती हैं। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2004 को शास्त्रीय भाषा के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया, जिसके तहत शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया तथा उसके बाद संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उडिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। एक सप्ताह की बयान ने कहा गया है कि 2013 में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का अनुरोध किया गया था। इस प्रस्ताव को भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति (एलईसी) ने भेज दिया गया था। एलईसी ने शास्त्रीय भाषा के लिए मराठी को सिफारिश की। महाराष्ट्र ने इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने के बाद इन राज्य को एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। बयान ने कहा गया कि इस बीच, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल से भी पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

पटाखा इकट्ठा विसफोट मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मृतकों की संख्या छह हुई

बरेली। अवैध पटाखा फैक्ट्री में विसफोट में छह लोगों की मौत के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को कहा कि मामले से चार पांच साल के दो बच्चों के शव निकले गए, जबकि घायलों में से एक सितार (32) ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही मरने वाली की संख्या बढ़कर छह हो गई। बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि विसफोट रचना शाह नामक व्यक्ति के घर पर हुआ, जिसके बाद एक बच्चे की मौत हुई। विसफोट तहत मरने वाले की संख्या बढ़ाने में मुख्य आरोपी नासिर शाह को बृहस्पतिवार को सिरोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएसीपी ने कहा कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि शाह के पास केवल पाचो बच्चे थे बा लाइसेंस है और वह अपने ससुर रजमान शाह के नकवान में अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। इनमें छह, जिनमें एक बच्चे की संख्या बढ़कर पांच हो गई थी। जबकि घायलों में से एक सितार (32) ने दैरा अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही मरने वाली की संख्या छह हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

भारत की यूपीआई की सफलता को दोहराना चाहता है जमैका: प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस

नई दिल्ली। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह डिजिटल गुगलान क्षेत्र में भारत की प्रौद्योगिकी प्रगति का लाभ उठाकर डिजिटल गुगलान में दक्षिण एशियाई देश की सफलता को दोहराना चाहते हैं। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए होलनेस ने डिजिटल व्यवस्था के बढ़ते हैं और वे जल्द ही उभरने के लिए डिजिटल इंडिया (डीआईई) के अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के साथ बैठक की। उन्होंने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, जबकि वे अपने विकास के विभिन्न तथ्यों में से एक डिजिटल रचना बनाने का लक्ष्य रखते हैं। हमने पहले ही अपनी राष्ट्रीय पहचान प्रणाली स्थापित कर ली है जो आपकी आधार प्रणाली के समान है। होलनेस ने कहा, उनका देश भारतीय प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और यूनिफाइड एकेडमि (यूपीआई) के साथ मजबूत साझेदारी विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, गोलनेस बैठक इस बात पर चर्चा करने के लिए थी कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और यूपीआई बुनियादी ढांचा जमैका से डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में कैसे मदद कर सकता है।

आईटी क्षेत्र में सुधार से सितंबर में नौकरी बाजार में छह प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली। दायर के बेतक्य काम करने वाली (सहस्ट्र-वैक्टर) नौकरियों के लिए गर्मी गतिविधियों में सितंबर में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में छह प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट ने कहा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में सुधार के कारण दायर के बेतक्य काम करने वाले वर्गों की निरूपितता बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, नौकरी बाजार में सुधार के कारण सितंबर में नौकरियों की वृद्धि 3.7 प्रतिशत से 2.72 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह सकारात्मक रजमान मुख्य रूप से सुधार कर रहे आईटी क्षेत्र के कारण आया। इस क्षेत्र में गर्मी गतिविधियों ने 18 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई और पारदर्शिक आईटी क्षेत्र ने उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो संचालित रूप से मौसमिक विविधीकरण का रजमान दिखाता है। रिपोर्ट के अनुसार, आईटी क्षेत्र ने गर्मी में सबसे ज्यादा 47 प्रतिशत की वृद्धि का रजमान देखा है। रिपोर्ट के अनुसार, आईटी क्षेत्र ने गर्मी में सबसे ज्यादा 47 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि तेल एवं गैस क्षेत्र नौकरियों 13 प्रतिशत बढ़ी।

इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के कस्बों और लोगों से जगह खाली करने को कहा



बेरूत में इजराइल के हवाई हमलों में ध्वस्त हुआ बड़ा बेश

● इजराइली हवाई हमले से मध्य बेरूत में सात लोगों की मौत

भाषा। बेरूत

इजराइल की सेना ने बृहस्पतिवार को दक्षिणी लेबनान के कस्बों और गांवों के लोगों से जगह खाली करने की चेतावनी दी। यह क्षेत्र 2006 के युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बफर जोन के उत्तर में स्थित है। इस चेतावनी से दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य काबाई के संभावित विस्तार का संकेत मिलता है, जो अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इजराइल ने लोगों से प्रांतीय राजधानी के वावजूद हमला हुआ। इंसने कहा कि तैबेह गांव के पास टीम को बृहस्पतिवार को निशाना बनाया गया, जिसमें लेबनानी सैनिक भी शामिल थे। इंसने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के समन्वय के साथ चलाए गए अभियान के बावजूद हमला हुआ। हालांकि, इजराइल की सेना ने इस मामले में तत्काल कोई टिप्पणी

बांग्लादेश को बिजली निर्यात के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर

भाषा। काठमांडू

बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए नेपाल, बांग्लादेश और भारत ने लंबे समय से प्रतीक्षित त्रिपक्षीय समझौते पर बृहस्पतिवार को हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। समझौते के अनुसार, नेपाल हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली का निर्यात करेगा। भारत, नेपाल से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट पनबिजली का निर्यात करेगा।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईएफ) के अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र दर 6.4 बिलियन डॉलर तक बढ़ेगा। बिजली की निर्यात से नेपाल को सालाना करीब 92 लाख डॉलर की आमदनी होगी। समझौते की शर्तों के अनुसार एनईए

कूटनीतिक फेरबदल के बीच बांग्लादेश ने भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाया

ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नई दिल्ली में अपने उच्चायुक्त सहित पांच दूतों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू प्रशासन के साथ-साथ राजनयिक सेवा में भी दूसरे चरण का फेरबदल किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मुख्य सलाहकार के रूप में प्रोफेसर मुहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने नवीनतम फेरबदल के तहत भारत, बुरुसेस, कैनबरा, लिस्बन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थाई मिशन में बांग्लादेश के दूतों को तत्काल वापस लौटने और यहाँ विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करने को कहा है। नाम न जाहिर करने की इच्छ व्यक्त करते हुए एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा, राजदूतों को वापस बुलाना सरकार के उस निर्णय का हिस्सा है जिसके तहत भारत में हमारे उच्चायुक्त मुस्तफिज़ुर रहमान को ढाका में विदेश मंत्रालय में वापस लौटने को

कहा गया है। लंदन में बांग्लादेश की उच्चायुक्त सादिया मुना तस्नीम को चार दिन पहले ढाका लौटने को कहा गया था। विदेश सेवा में अगस्त के अंत में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया, जो 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए व्यापक जन-विद्रोह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन को हटाए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुआ। इस विद्रोह के बाद आठ अगस्त को नोबेल पुरस्कार विजेता का अंतरिम प्रशासन स्थापित हो गया। उस समय ढाका ने अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में अपने राजदूतों और मालदीव में अपने उच्चायुक्त को स्वदेश लौटने का आदेश दिया था। इनमें से कई राजदूत पूर्व राजनयिक या सेवानिवृत्त एवं सेवारत प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी थे, जिन्हें अपदस्थ सरकार द्वारा विदेश में नियुक्त किया गया था।

इस बीच, कार्यभार संभालने के

बाद अंतरिम सरकार ने घरेलू प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों या शीर्ष नौकरशाहों की संविदा नियुक्तियों को रद्द कर दिया, जबकि मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रमुख सहित कई पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उन पर जुलाई और अगस्त के शुरू में हुए सरकार का कहर जारी है जिससे आम जनजीवन बाधित हो गया है। क्रैथॉन तुफान से बुरी तरह प्रभावित पिंगटन प्रांत के एक अस्पताल में आग लगी।

गृह मंत्रालय के बर्खास्त वरिष्ठ सचिव जहांगीर अलम और बर्खास्त पुलिस प्रमुख चौधुरी अब्दुल्ला अल मामून दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और छात्र आंदोलन के तहत हुए घातक विरोध प्रदर्शनों के दौरान उनकी गतिविधियों के लिए पूछताछ के वास्ते पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस आंदोलन में लगभग 1,000 लोगों की जान चली गई थी।

लेबनान में हिजबुल्ला के लगभग 200 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें हथियार भंडारण सुविधाएं और निगरानी चौकियां शामिल हैं। इंसने कहा कि हमलों में हिजबुल्ला के कम से कम 15 लड़ाके मारे गए। हिजबुल्ला ने कहा कि जब इजराइली सेना लेबनान के सीमावर्ती गांव मारून अल-रस में घुसी तो उसके लड़ाकों ने सड़क किनारे बम विस्फोट किया, जिसमें कई सैनिक मारे गए और घायल हुए। दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

बांग्लादेशी मंत्री सईदा वृधवार को बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय

कांगो में नौका पलटने से 50 लोगों की मौत

गोमा (कांगो)। मध्य अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी हिस्से में किवु झील में बृहस्पतिवार को सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक नौका के पलट जाने से कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह जानकारी दी। यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नौका पर कितने लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने बचाव सेवाओं को पानी से कम से कम 50 शव निकालते देखे। उन्होंने बताया कि 10 लोग बचा लिए गए और उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नौका पर क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। किटुकू बंदरगाह से कुछ मीटर की दूरी पर नौका डूब गई। यह घटना उस वक़्त हुई जब नौका दक्षिण किवु प्रांत के मिनोवा से उत्तर किवु प्रांत के गोता जा रही थी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य जारी है और मृतकों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। तुर्चेन्टा के बाद दक्षिण किवु प्रांत के गवर्नर जीन-जैक्स पुस्क्री से एक स्थानीय रैंड्यो स्टेशन को बताया, नौका पर करीब 100 लोग सवार थे।

कांगो में नौका पलटने से 50 लोगों की मौत



ताइवान में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के साथ तूफान क्रैथॉन ने दस्तक दी

काऊशुंग (ताइवान)। तूफान क्रैथॉन ने बृहस्पतिवार को ताइवान के प्रमुख बंदरगाह शहर काऊशुंग में दस्तक दी, जिससे द्वीप के दक्षिणी हिस्से में मूसलाधार बारिश हुई और तेज हवाएं चलीं। क्रैथॉन की वजह से चली तेज़ हवाओं के कारण पेड़ गिर गए और सड़कें जलमन हो गईं, जिससे स्कूल और कारोबारी प्रतिष्ठानों को बंद करना पड़ा। केंद्रीय मौसम प्रशासन ने बताया कि क्रैथॉन ने दोपहर करीब 12:40 बजे काऊशुंग के औद्योगिक सियाओगांग जिले में दस्तक दी। इसमें अधिकतम 126 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं निरंतर चलें और उनकी गति बढ़ कर 162 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गईं।

इस तूफान के राजधानी ताइपे पहुंचने से पहले धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ने, शुक्रवार तक कमजोर होकर उष्णकटिबंधीय दबाव में बदलने, और फिर ताइवान जलडमरूमध्य से होते हुए चीनी तट की ओर बढ़ने का अनुमान था। ताइपे में बृहस्पतिवार को तेज हवाएं चलीं लेकिन बारिश बहुत कम हुई।

लंदन में बांग्लादेशी मंत्री सईदा वृधवार को बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय

नेपाल के पीएम ने बांग्लादेशी मंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

भाषा। काठमांडू

प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और बांग्लादेश की वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन मंत्री सईदा रिजवाना हसन ने बृहस्पतिवार को यहां द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं की मुलाकात काठमांडू के बालूवातार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर हुई। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार बैठक के दौरान ओली और हसन ने दोनों देशों के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत और विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने अन्य क्षेत्रों के अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

बांग्लादेशी मंत्री सईदा वृधवार को बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच त्रिपक्षीय

ब्रिटेन ने चागोस द्वीपसमूह मॉरीशस को दिया, सैन्य अड्डा अपने पास रखा

लंदन। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित और लंबे समय से विवादित चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपे जाने के ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया। समझौते के तहत डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन-अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा बरकरार रहेगा। यह समझौता डिएगो गार्सिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्रिटेन-अमेरिका सैन्य अड्डे के निरंतर संचालन के लिए लिए किया गया है। चागोस, हिंद महासागर में 60 से अधिक द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।

ब्रिटेन सरकार ने एक बयान में कहा कि इस समझौते को अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय साझेदारों का पुरजोर समर्थन प्राप्त है। इस सप्ताह घोषित समझौते के तहत, क्षेत्र की स्थिरता एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला डिएगो गार्सिया कम से कम अगले 99 वर्षों तक ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर ने

पश्चिम एशिया के संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक की

संयुक्त राष्ट्र। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के दौर पर ध्यान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुधवार को एक आपातकालीन बैठक की। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि उनके देश ने मंगलवार को इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी थी, इजराइल की हिंसा को रोक़ा जा सके, जबकि उनके इजराइली समकक्ष ने इस हमले को आक्रमकता का अभूतपूर्व कृत्य करार दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया, वहीं एक इंगनी कमांडो ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो वे बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले करेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर किार जाने वाले इजराइली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल ने बुधवार

को तब और खलबली मचा दी जब उसके विदेश मंत्री ने संयुक्त गष्ट महासचिव को देश में अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया और संगठन के खिलाफ दशकों से लगे रहे यहूदी विरोधी आरोपों को दोहराया। इजराइल के खिलाफ दशकों से लगे रहे यहूदी विरोधी आरोपों को दोहराया। इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी थी, इजराइल की हिंसा को रोक़ा जा सके, जबकि उनके इजराइली समकक्ष ने इस हमले को आक्रमकता का अभूतपूर्व कृत्य करार दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया, वहीं एक इंगनी कमांडो ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो वे बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले करेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर किार जाने वाले इजराइली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल ने बुधवार

को तब और खलबली मचा दी जब उसके विदेश मंत्री ने संयुक्त गष्ट महासचिव को देश में अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया और संगठन के खिलाफ दशकों से लगे रहे यहूदी विरोधी आरोपों को दोहराया। इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी थी, इजराइल की हिंसा को रोक़ा जा सके, जबकि उनके इजराइली समकक्ष ने इस हमले को आक्रमकता का अभूतपूर्व कृत्य करार दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया, वहीं एक इंगनी कमांडो ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो वे बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले करेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने बुधवार को कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाकर किार जाने वाले इजराइली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इजराइल ने बुधवार

को तब और खलबली मचा दी जब उसके विदेश मंत्री ने संयुक्त गष्ट महासचिव को देश में अवांछनीय व्यक्ति घोषित कर दिया और संगठन के खिलाफ दशकों से लगे रहे यहूदी विरोधी आरोपों को दोहराया। इजराइल पर लगभग 200 मिसाइल दागी थी, इजराइल की हिंसा को रोक़ा जा सके, जबकि उनके इजराइली समकक्ष ने इस हमले को आक्रमकता का अभूतपूर्व कृत्य करार दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात जवाबी कार्रवाई करने का संकल्प व्यक्त किया, वहीं एक इंगनी कमांडो ने धमकी दी कि अगर इजराइल ने ऐसा किया तो वे बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले करेंगे।

अमेरिका के सिएटल सेंटर में गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया

वाशिंगटन। अमेरिका के सिएटल सेंटर में महान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महात्मा गांधी की जयंती पर उनकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिएटल के मेयर ब्रूस हैंरैल, सांसद एडम सिम्थ और भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल की उपस्थिति में बुधवार को आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिएटल में स्थापित गांधी की यह पहली आवक्ष प्रतिमा है। प्रतिमा को लोकप्रिय स्पेस नीडल के नीचे तथा चिहुली गार्डन एवं ग्लास म्यूजियम के समीप स्थापित किया गया है। प्रतिमा के अनावरण समारोह का नेतृत्व सिएटल में भारत के महावाणिज्यदूत प्रकाश गुप्ता ने किया। समारोह में उत्तर पश्चिम प्रशांत में यूएस फर्सट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जेवियर ब्रूनसन और मार्टिन लूथर किंग गांधी इनिशिएटिव के अध्यक्ष एडी राई भी शामिल हुए थे। गांधी जयंती समारोह में शामिल हुए गणमान्य अतिथियों ने अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय के मूल्यों को रेखांकित किया और इन मूल्यों की समकालीन समय में बेहद जरूरी बताया। इस अवसर पर, वाशिंगटन के गवर्नर जे. इंस्टली ने एक आधिकारिक घोषणा जारी की। उन्होंने इस प्रतिमा को गांधी के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धांजलि बताया और कहा कि यह प्रतिमा अहिंसा के मार्ग पर चलकर परिवर्तन लाने के प्रभाव को याद दिलाएगी।

घोषणा में कहा गया है कि महात्मा गांधी की यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से सिएटल शहर को उपहार है, जो गांधी के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धांजलि होगी तथा सामाजिक एवं राजनीतिक बदलाव प्राप्त करने में अहिंसा की ताकत को याद दिलाएगी। वाशिंगटन राज्य की ओर से जारी घोषणा में कहा गया है कि शांति, सहिष्णुता और जात की संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत राज्य सिएटल शहर ने महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा के अनावरण की सराहना करता है। यह भारत की ओर से एक ऐसा उपहार है, जो इन मूल्यों के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है और राज्य मानवता पर गांधी के गहन प्रभाव का सम्मान करता है।

घोषणा में कहा गया है कि वाशिंगटन राज्य में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की आबादी 2,00,000 से अधिक है, जिनका राज्य के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने में योगदान अमूल्य है। किंग काउंटी ने भी ग्रेटर सिएटल क्षेत्र के सभी 73 शहरों में दो अक्टूबर को महात्मा गांधी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। किंग काउंटी की घोषणा में कहा गया है कि गांधी के जीवन और शांति एवं अहिंसा के उनके मार्ग ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। घोषणा में कहा गया है कि गांधी के विरोध के अहिंसक तरीके या सत्याग्रह के उनके दर्शन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और न्याय, समानता एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हुए वैश्विक स्तर पर कई नागरिक अधिकार आंदोलनों को प्रभावित किया।

घोषणा के अनुसार, 1986 में किंग काउंटी कार्डिसिल ने महात्मा गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांत के प्रबल अनुयायी डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नाम पर काउंटी का आधिकारिक नाम किंग काउंटी रखने का प्रस्ताव दिया। घोषणा में मार्टिन लूथर किंग के उस वक्तव्य का जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था, मैं अन्य देशों में एक पर्यटक के रूप में जा सकता हूं, लेकिन भारत में मैं एक तीर्थयात्री के रूप में जाऊंगा। सिएटल में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले साल नवंबर में प्रशांत उत्तर-पश्चिम के नौ ग्रन्थों वाशिंगटन, ओरेगन, इडाहो, मोंटाना, व्योमिंग, नार्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का और अलास्का में वाणिज्य दूतावास के साथ परिचालन शुरू किया था। वाणिज्य दूतावास ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सिएटल में गांधी की प्रतिमा की स्थापना उसके वाणिज्य दूतावास क्षेत्राधिकार में क्रियान्वित की जा रही पहलों की श्रृंखला में से एक है। दूतावास ने एक विज्ञप्ति में कहा, भारत के महावाणिज्य दूतावास और सिएटल शहर ने महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान को चिह्नित करने के लिए मिलकर काम किया और प्रतिष्ठित सिएटल सेंटर के इस स्थान को उपयुक्त माना गया। हर साल यहां 1.2 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं। स्थान और लोगों की पहुंच तथा शांति एवं अहिंसा के मूल्यों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रतिमा की स्थापना के लिए सिएटल सेंटर को उपयुक्त समझा गया। गांधी की जयंती को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

ताइवान के अस्पताल में आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत

ताइपे (ताइवान)। दक्षिणी ताइवान के एक अस्पताल में बृहस्पतिवार की सुबह आग लगने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। इस द्वीप पर तूफान का कहर जारी है जिससे आम जनजीवन बाधित हो गया है। क्रैथॉन तुफान से बुरी तरह प्रभावित पिंगटन प्रांत के एक अस्पताल में आग लगी।

अस्पताल से दर्जनों अन्य मरीजों को सुरक्षित निकालकर पास के शरण स्थलों में ले जाया गया। मरीजों को निकालने और आग बुझाने में चिकित्साकर्मियों तथा दमकल कर्मियों की सहायता के लिए सैनिकों को बुलाया गया। खबर के अनुसार 176 मरीजों को सामने के प्रवेश द्वार पर ले जाया गया और उन्हें मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए एंबुलेंस या तिरपाल के माध्यम से पास

के आश्रय स्थलों में ले जाया गया। ताइवान के मौसम अधिकारियों के अनुसार, क्रैथॉन ने प्रमुख बंदरगाह शहर काऊशुंग में दस्तक दी और हवा की गति 126 किलोमीटर प्रति घंटा थी।

पिछले पांच दिनों में तूफान के प्रभाव के कारण हुई बारिश से द्वीप के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से जलमन हो गए हैं, जिससे पर्वतीय या निचले इलाकों के हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी पड़ी। द्वीप के आस-पास के स्कूल और सरकारी दफ्तर दो दिनों से बंद हैं और सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ और तेज हवाओं ने मछुआरों से लेकर रसायन उद्योग तक को काफी नुकसान पहुंचाया है, जबकि परिवहन मार्ग और बिजली आपूर्ति भी ठप पड़ गई हैं। ताइवान ने हाल के वर्षों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर हुई भवन निर्माण के कार्यान्वयन को बढ़ावा देकर सार्वजनिक सुविधाओं को अग्निरোধक बनाने में काफी प्रगति की है।

अमेरिका-भारत सीईओ फोरम ने द्विपक्षीय व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका-भारत सीईओ मंच ने द्विपक्षीय व्यापार तथा वाणिज्य का विस्तार करने, समावेशी आर्थिक वृद्धि और नवाचार को बढ़ाने के साथ मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के इस मंच की सह-अध्यक्षता अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमॉडो और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। मंच का छठा संस्करण बुधवार को अमेरिकी राजधानी में आयोजित किया गया। एक एएस मंच है जो द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने तथा दोनों देशों के बीच व्यापार व निवेश का विस्तार करने के उद्देश्य से संयुक्त सिफारिशों करने के लिए अमेरिका और भारत के व्यापार जात के लोगों को एक साथ लाता है।

लॉकहीड मार्टिन के सीईओ एवं अध्यक्ष जेम्स टेसलेट और टटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन 2023-2024 के लिए निजी क्षेत्र के सह-अध्यक्ष हैं। बैठक के दौरान, रायमॉडो और गोयल ने पिछले दो वर्षों में मंच के सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों और उनकी पहलों को सराहना भी की। गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, भारत-अमेरिका सीईओ मंच में दोपहर के भोजन पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री रायमॉडो के साथ एक सार्थक बैठक हुई। हमारी स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान व विकास सहयोग की संभावनाओं पर केंद्रित रही।

उन्होंने कहा, हमने आपसी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत के आगामी 20 औद्योगिक शहरों में अमेरिकी निवेश के अवसरों पर भी उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। अमेरिका और भारत के बीच समावेशी वृद्धि के लिए नवाचार और निवेश व व्यापार को दोहन हेतु सार्वजनिक रूप से सुलभ नेटवर्क (एनआईएचआईटी) मंच की शुरुआत भी की गई। इस मंच का मकसद अमेरिकी और भारतीय स्टार्टअप तथा छोटे व्यवसायों के बीच ऑनलाइन जानकारी साझा करना और संपर्क को सुविधाजनक बनाना है। प्रेस विज्ञापित के अनुसार, एनआईएचआईटी ने साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों तथा एआई क्षमता निर्माण व कौशल को बढ़ावा देने के लिए अब तक चार कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इनमें 1,000 से अधिक स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और उद्यमियों ने हिस्सा लिया। मंच के सदस्य 22 अमेरिकी कंपनियों और 25 भारतीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

